শৰ্মা হাৰ্ডৱেৰ
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in | हिंदी दैनिक | गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 11 | अंक : 123 | गुवाहाटी | सोमवार, 2 दिसंबर, 2024 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

हम भी दो-तीन चीजों के अध्ययन के लिए टीमें झारखंड भेजेंगे — पेज 2
बांग्लादेश : हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में राज्य में प्रदर्शन — पेज 3
जबरन किसी का धर्मांतरण न हो, ऐसा कानून होना ही चाहिए : मंत्री शेखावत — पेज 5
यूएसपीएल सीजन 3 : न्यू जर्सी टाइटंस को हरा न्यूयॉर्क काउबॉयज फाइनल में — पेज 7

कांग्रेस तैयार है तो राज्य में गोमांस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देंगे : सीएम

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्व शर्मा ने कहा है कि अगर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख भूपेन कुमार बोरा उन्हें पत्र लिखकर गोमांस पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करें तो वह राज्य में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। दरअसल मुस्लिम बहुल सामागुड़ी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान भाजपा पर गोमांस बांटने का आरोप लगा है। इस उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर पहले लगातार पांच बार कांग्रेस को जीत मिली थी। असम के मुख्यमंत्री से जब शनिवार को जब कांग्रेस के आरोपों पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि सामागुड़ी सीट 25 साल तक कांग्रेस के पास रही। सामागुड़ी जैसे निर्वाचन क्षेत्र में 27,000 मतों के अंतर से हारना कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी शर्म की बात है। यह भाजपा की जीत से ज्यादा कांग्रेस की हार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख के बीच रकीबुल हुसैन ने एक अच्छी बात कही कि गोमांस खाना गलत है, है न? उन्होंने कहा है कि मतदाताओं को गोमांस परोसकर कांग्रेस-भाजपा का चुनाव जीतना गलत है। शर्मा ने सवाल किया कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस मतदाताओं को गोमांस की पेशकश करके ही अब तक सामागुड़ी जीत रही थी। वह सामागुड़ी को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि गोमांस की पेशकश करके सामागुड़ी जीता जा सकता है? सीएम शर्मा ने कहा कि मैं रकीबुल हुसैन से कहना चाहता -शेष पृष्ठ दो पर

न्यायालय के नए भवन से न्यायपालिका की कार्यकुशलता बढ़ेगी : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने आज कछार जिले के लखीपुर में उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (एम) न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय भवन के उद्घाटन से न केवल लखीपुर और कछार जिले में न्यायपालिका की कार्यकुशलता बढ़ेगी, बल्कि बराक घाटी में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब लखीपुर को सह-जिला के रूप में मान्यता मिल गई है, इसलिए इस नए न्यायिक भवन से क्षेत्र में न्यायपालिका के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी से पहले बराक घाटी के हृदयस्थल कछार जिले का न्यायिक प्रशासन सिलहट सदर कोर्ट के अधीन था, जबकि सिलचर में एक सर्किट कोर्ट संचालित होता था। हालांकि, आजादी के बाद अविभाजित कछार जिला जोरहाट जिले और सदर जज के अधिकार क्षेत्र में आ गया। डॉ. शर्मा ने कहा कि जिले की कानूनी जरूरतों को पूरा करने और इसके न्यायिक ढांचे का विस्तार करने के लिए 1955 में कछार के लिए जिला जज का एक अलग और स्वतंत्र पद बनाया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वर्तमान राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, राज्य में न्यायिक बुनियादी ढांचे ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सक्रिय कदमों पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने बरपेटा और शिवसागर जिलों में नए जिला न्यायिक न्यायालय भवनों का निर्माण और -शेष पृष्ठ दो पर

एएमसीएच के छात्रावास में खाद्य विषाक्तता, कई छात्र बीमार

डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ स्थित असम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एएमसीएच) के लड़कों के छात्रावास के कई छात्र कथित तौर पर बीमार पड़ गए हैं, जिससे संभावित खाद्य विषाक्तता फैलने की चिंता पैदा हो गई है। यह घटना मेडिकल संस्थान के 225 बिस्तरों वाले छात्रावास में हुई। सूत्रों के अनुसार, स्वास्थ्य संबंधी चिंता तब शुरू हुई जब एक छात्र ने दस्त और पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद सात अन्य छात्रों में उल्टी और गैस संबंधी लक्षण दिखाई दिए। प्रभावित छात्रों ने कॉलेज की आपातकालीन इकाई में तत्काल -शेष पृष्ठ दो पर

16 आरक्षित वनों में अतिक्रमण पर एनजीटी ने असम के मुख्य वन संरक्षक से मांगा जवाब

नई दिल्ली। असम के कामरूप महानगर जिले में वन भूमि के अतिक्रमण मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक से जवाब तलब किया है। अधिकरण ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें दावा किया गया कि जिले में 35,329 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले 16 आरक्षित वनों के एक बड़े हिस्से पर अतिक्रमण किया गया है। जिले के अवैध अतिक्रमणों में फाटाशिल, दक्षिण कालापहाड़, जालुकबाड़ी, गोटानगर, हेंगराबाड़ी, शरणिया और गड़भांगा जैसी पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ियां शामिल हैं। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए संथिल वेल की पीठ ने 19 नवंबर को जारी एक आदेश में रिपोर्ट पर गौर करते हुए कहा कि जंगलों पर अतिक्रमण के -शेष पृष्ठ दो पर

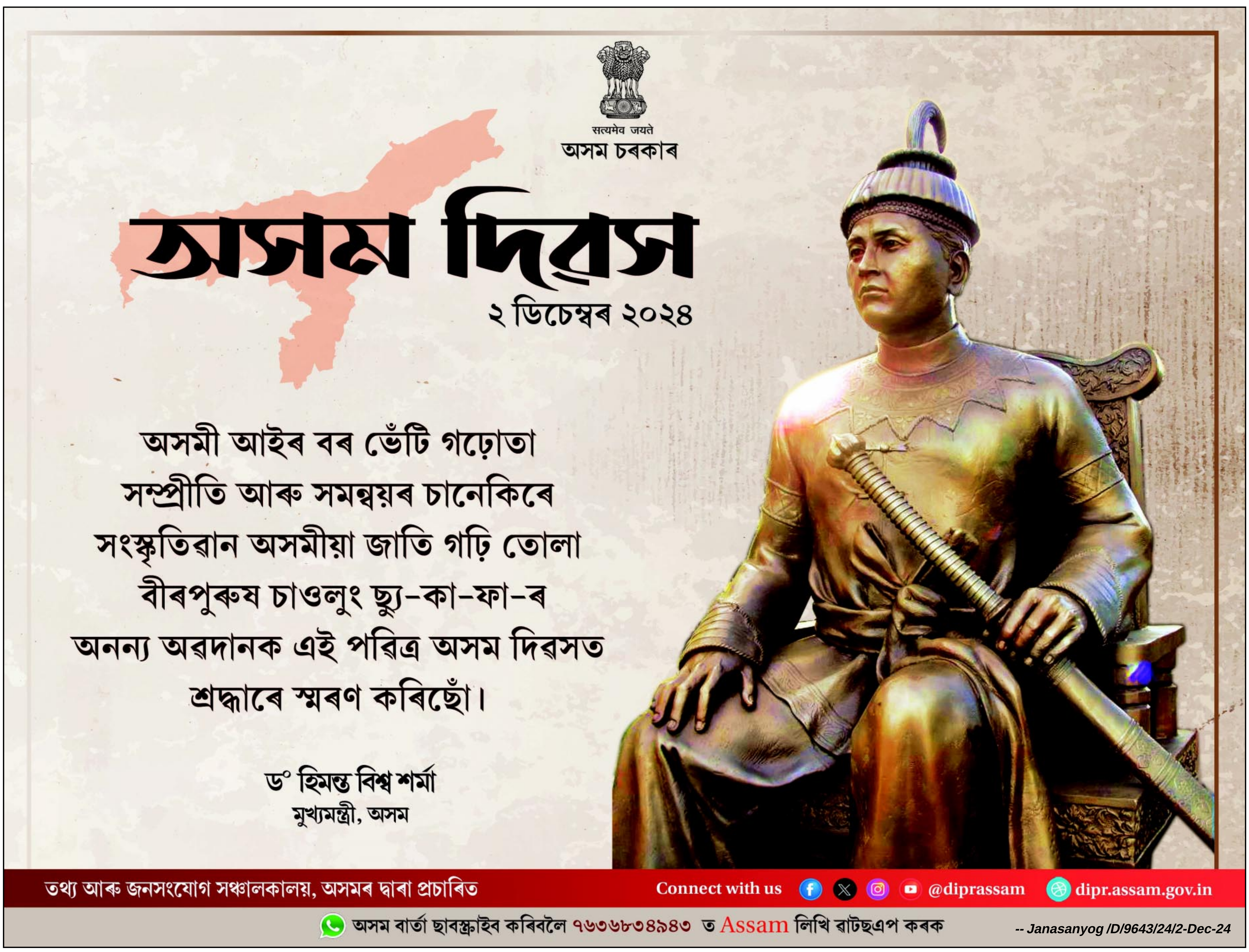

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivling, Nandi etc. **ARTCLE WORLD,** S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, **Ph. : 94350-48866, 94018-06952**

हेमंत बनाम हिमंत : सोरेन के एलान के बाद, असम सीएम बोले-

हम भी दो-तीन चीजों के अध्ययन के लिए टीमें झारखंड भेजेंगे

गुवाहाटी। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी झारखंड सीएम हेमंत सोरेन और असम सीएम हिमंत विश्व शर्मा के बीच वार-पलटवार का दौर जारी है। अब असम सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि वह भी असम की दो टीमें झारखंड में दो-तीन चीजों का अध्ययन करने के लिए भेजेंगे। असम सीएम का यह बयान ऐसे समय आया है, जब हाल ही में झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने असम में चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की दुर्दशा का अध्ययन करने के लिए सर्वदलीय टीम भेजने का एलान किया है। शनिवार रात को भाजपा नेताओं की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए हिमंत शर्मा ने कहा कि 5 दिसंबर को हमारी कैबिनेट में झारखंड के कुछ इलाकों का दौरा करने का फैसला किया जाएगा। हम वहां जाएंगे और दो-तीन चीजें देखेंगे। हालांकि हिमंत ने उन चीजों के बारे में नहीं बताया, जिनके अध्ययन के लिए उन्होंने टीमें भेजने की बात कही है। गौरतलब है कि हिमंत विश्व शर्मा झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के चुनाव सह-प्रभारी रहे थे। चुनाव के दौरान हिमंत विश्व शर्मा ने जहां झारखंड में अवैध घुसपैठ को मुद्दा बनाया था। वहीं हेमंत सोरेने के नेतृत्व वाली झामुमो ने असम में चाय बागानों में काम करने वाले जनजातियों श्रमिकों की दुर्दशा को मुद्दा बनाने की कोशिश की। अब जब झारखंड चुनाव में झामुमो के नेतृत्व में इंडी गठबंधन सत्ता में आ चुका है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ लेते ही एक सर्वदलीय दल को असम भेजकर चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की दुर्दशा का अध्ययन कराने का फैसला किया है। अब माना जा रहा है कि इसी के जवाब में असम सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने भी दो टीमें झारखंड भेजने का एलान कर दिया है। साफ है कि दोनों नेताओं के बीच झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई तनातनी अभी भी जारी है। 25 सितंबर को हेमंत सोरेन ने हिमंत विश्व शर्मा को पत्र लिखकर दावा किया था कि असम के चाय बागानों में काम करने वाली झारखंड की जनजातियों के लोगों को हाशिए पर रखा गया है, जबकि अर्थव्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। सोरेन ने जनजातीय समुदाय की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी और उन्हें एसटी के रूप में मान्यता देने की वकालत की थी। असम में चाय जनजाति को अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा प्राप्त है। असम में मोरन, मोटोक, चुटिया, ताई-अहोम, कोच-राजबोंगशी और चाय जनजाति समुदाय वर्षों से एसटी का दर्जा मांग रहे हैं। हेमंत सोरेन ने असम में झारखंड के सभी मूल निवासियों से वापस लौटने की अपील भी की है। झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन लगातार दूसरी बार सत्ता में आया और 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 24 सीटें मिलीं।

बच्चे की मौत

नगांव (हिंस)। जिले के रुपहीहाट के हातीपारा में एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि ट्रैक्टर (एएस- 02सीसी- 4999) की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। हातीपारा में जीएल एटाभाटा के पास यह हादसा हुआ। घटना उस समय हुई जब बच्चा रास्ते पर खेल रहा था। पुलिस ने बाद में मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया।

तीन से अधिक बच्चों को पैदा की जरूरत

मोहन भागवत के बयान पर मचा घमासान, विपक्ष ने उठाए सवाल

मुंबई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला देते हुए बताया कि जब किसी समाज की जनसंख्या (प्रजनन दर) 2.1 से नीचे चला जाता है तो वह समाज धीरे-धीरे पृथ्वी से लुप्त होने की कगार पर होता है। भागवत ने आगे कहा कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है। हालांकि, उनके इस बयान पर विपक्ष ने प्रतिक्रिया दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या (प्रजनन दर) 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज पृथ्वी से लुप्त हो जाता है। संकट न होने पर भी वह समाज नष्ट हो जाता है। इस तरह अनेक भाषाएं और समाज नष्ट हो गए। जनसंख्या 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। हमारे देश की जनसंख्या नीति 1998 या 2002 में तय की गई थी। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी समाज की जनसंख्या 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या विज्ञान का कहना है कि हमें दो या तीन से अधिक बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है। समाज को जीवित रखने के लिए संख्या महत्वपूर्ण है। मोहन भागवत के बयान पर समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से मोहन भागवत जो कुछ कहते हैं, उससे भाजपा को असहज हो जाती है। पिछली बार भी जब मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना, तब भी भाजपा के पास कोई जवाब नहीं था। भाजपा पूरे देश की जनसंख्या को लेकर राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता उमंग सिंघर ने भी मोहन भागवत के बयान पर सवाल उठाए।

भारतवंशी काश पटेल को ट्रम्प ने बनाया एफबीआई का डायरेक्टर

वाशिंगटन (हि.स.)। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतवंशी कश्यप काश पटेल को जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (एफबीआई) का अगला डायरेक्टर नियुक्त किया है। ट्रम्प ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रूथ सोशल पर इसकी घोषणा की। पोस्ट में ट्रम्प ने काश पटेल के पिछले कामों की तारीफ भी की। ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान काश पटेल रक्षा मंत्रालय में चीफ ऑफ स्टाफ, नेशनल इंटेलिजेंस में डिप्टी डायरेक्टर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद विरोधी कार्यक्रमों के सीनियर डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। ट्रम्प के बेहद भरोसेमंद भारतवंशी काश पटेल एफबीआई डायरेक्टर पद पर 20 जनवरी 2025 को नई सरकार के कार्यकाल के साथ काबिज हो जाएंगे। ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि कश्यप *काश* एफबीई के अगले निदेशक के रूप में काम करेंगे। काश एक शानदार वकील, इंवेस्टिगेटर और *अमेरिका फर्स्ट* वॉरियर हैं, जिन्होंने अपना करियर भ्रष्टाचार उजागर करने, न्याय की रक्षा करने और अमेरिकी लोगों की रक्षा करने में बिताया है। काश पटेल का पूरा नाम कश्यप पटेल है। उनके माता-पिता का जीवन युगांडा में बीता। उनके पिता 70 के दशक में बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका आ गए थे।

गांजा की खेती करने वाला किसान गिरफ्तार

दक्षिण सालमारा- मानकाचर (हिंस)। जिले के कनाईमारा में गांजा की खेती करने वाले किसान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किसान लाल मियां अपने घर के नजदीक करीब 10 बीघा भूमि पर गांजे की खेती कर रहा था। पुलिस ने रविवार को बताया कि दक्षिण सालमारा मानकाचर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रताप दास के नेतृत्व में खरुबंधा पुलिस की एक टीम ने छापा मारा और गांजा की खेती करने वाले किसान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गांजा की खेती करने वाले किसान लाल मियां को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। गांजे के खेत में लगे सभी पेड़ों को भी पुलिस ने काटकर जला दिया।

जब तक कुछ हाथों में ही पैसा रहेगा, तरक्की नहीं हो सकती : राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को भारत की जीडीपी विकास दर के दो साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने पर चिंता जताई और कहा कि जब तक कुछ अरबपति ही इसका लाभ उठाते रहेंगे, तब तक देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए नई सोच की जरूरत है और कारोबार के लिए एक नया समझौता उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर दो साल में सबसे नीचे 5.4 फीसदी पर आ गई है। बात साफ है- भारतीय अर्थव्यवस्था तब तक तरक्की नहीं कर सकती, जब तक इसका फायदा सिर्फ गिने-चुने अरबपतियों को मिल रहा हो और किसान, मजदूर, मध्यमवर्ग और गरीब तरह-तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हों। तथ्यों पर नजर डालिए, देखिए स्थिति कितनी चिंताजनक है। उन्होंने आगे लिखा कि खुदरा महंगाई दर बढ़कर 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21 फीसदी पर पहुंच गई है। पिछले साल अक्तूबर की तुलना में इस वर्ष आलू और प्याज की कीमत लगभग 50 फीसदी बढ़ गई है। रुपया 84.50 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बेरोजगारी पहले ही 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा कि पिछले पांच वर्षों में मजदूरों, कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों की आमदनी या तो ठहर गई है या काफी कम हो गई है। उन्होंने लिखा कि आमदनी कम होने से मांग में भी कमी आई है। 10 लाख से कम कीमत वाले कारों की बिक्री में हिस्सेदारी घटकर 50 फीसदी से कम हो गई है, जो 2018-19 में 80 फीसदी थी।

नवंबर में 1.82 लाख करोड़ रुपए का हुआ जीएसटी संग्रह

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में सकल जीएसटी संग्रह 8.5 प्रतिशत बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। जीएसटी संग्रह बढ़ने के पीछे की वजह घरेलू लेनदेन के कारण मिला अधिक राजस्व है। रविवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 34,141 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 43,047 करोड़ रुपए, एकीकृत आईजीएसटी 91,828 करोड़ रुपए और उपकर 13,253 करोड़ रुपए रहा। नवंबर में कुल सकल जीएसटी राजस्व 8.5 प्रतिशत बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 1.68 लाख करोड़ रुपए था। अक्तूबर में 1.87 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह नौ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ दूसरा सबसे अच्छा जीएसटी संग्रह था। अब तक का सबसे अधिक संग्रह अप्रैल, 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। समीक्षाधीन महीने के दौरान घरेलू लेनदेन से जीएसटी राजस्व 9.4 प्रतिशत बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपए हो गया।

पृष्ठ एक का शेष

कांग्रेस तैयार है ...

हूं कि गोमांस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि यह गलत है। उन्हें मुझे केवल लिखित में देने की जरूरत है कि न तो भाजपा और न ही कांग्रेस को गोमांस के बारे में बोलना चाहिए, बल्कि असम में इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, तो सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। सामागुड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के दिप्लू रंजन शर्मा ने कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन के बेटे तंजील को 24,501 मतों के अंतर से हराया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह रकीबुल हुसैन के बयान को लेकर गोमांस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का रुख जानने के लिए उन्हें पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भूपेन बोरा को पत्र लिखकर पूछूंगा कि क्या वह भी रकीबुल हुसैन की तरह गोमांस पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हैं, और अगर ऐसा है तो मुझे बता दें। मैं गोमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दूंगा। उल्लेखनीय है कि असम में गोमांस का सेवन गैरकानूनी नहीं है, लेकिन असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 के तहत हिंदू, जैन और सिखों की बहुसंख्या वाले क्षेत्रों तथा किसी मंदिर या वैष्णव मठ के पांच किलोमीटर के दायरे में मवेशी वध और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध है।

न्यायालय के नए भवन...

उद्घाटन किया है। इसी तरह, 23 नवंबर को गोलाघाट जिले के अंतर्गत बोकाखात में सब डिवीजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट भवन का भी उद्घाटन किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि ये नए न्यायालय भवन, न्यायाधीशों के लिए कोर्ट रूम और चैंबर के अलावा, पुस्तकालय, वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम, विभिन्न कार्यालय स्थान, एक कमजोर गवाह बयान केंद्र, ध्यान कक्ष और सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इसके अलावा, धुबड़ी, ग्वालपाड़ा, तिनसुकिया और गोहपुर में कोर्ट कॉम्प्लेक्स और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण तेजी से चल रहा है। ग्वालपाड़ा और दरंग जिलों में कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही, कार्बी आंग्लांग के डिफू में बन रहे कोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा, दक्षिण सलमारा-मनकाचर, बजाली, बिश्वनाथ, माजुली और पश्चिम कार्बी आंग्लांग के नवगठित जिलों में जिला न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के *न्याय में सुगमता* के विजन को साकार करने के लिए सभी कदम उठा रही है। न्यायपालिका को आम लोगों के करीब लाने के लिए राज्य सरकार ने न्याय को और सुलभ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को यौन शोषण से बचाने और बाल विवाह से संबंधित मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए 17 जिलों में पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालतें स्थापित की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नगांव जिले में ऐसी दो अदालतें स्थापित की गई हैं। राज्य के आर्थिक विकास के साथ ही वाणिज्यिक विवादों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसलिए गुवाहाटी में एक समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इसी तरह एक विशेष एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) अदालत की भी योजना बनाई जा रही है। राज्य में अभियोजन निदेशालय स्थापित करने के भी प्रयास चल रहे हैं, जो अभियोजन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यों के नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। डॉ. शर्मा ने यह भी कहा कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कैदियों की संख्या कम करने के लिए राज्य सरकार ने छोटे-मोटे मामलों को वापस लेने के उपाय लागू किए हैं। इस पहल के तहत इस साल मार्च तक करीब 81,000 छोटे-मोटे मामले वापस लिए गए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गवाहों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित बयान केंद्र स्थापित किए गए हैं और इनमें से कई केंद्र पहले से ही चालू हैं। राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डालते हुए डॉ. शर्मा ने कहा कि संकटग्रस्त महिलाओं को सस्ती कानूनी जानकारी और आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए ई-सेवा केंद्र और मोबाइल ऐप *बोरशा* शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि कानूनी बिरादरी की जिम्मेदारी है कि वे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में मुकदमे में देरी करने के लिए खामियों का इस्तेमाल न करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) को लाकर अपने कानूनी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत की है। इस नए कानूनी ढांचे ने एक अधिक कुशल और प्रौद्योगिकी-संचालित न्यायिक प्रक्रिया की सुविधा प्रदान की है, जिससे न्याय प्रदान करना आसान हो गया है और न्यायिक प्रणाली पर अत्यधिक मामलों का बोझ कम हो गया है। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन आपराधिक न्याय प्रणाली के परिवर्तन को उजागर करते हैं, जो कानूनी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। डॉ. शर्मा ने यह भी कहा कि भारतीय सांख्यिकी अधिनियम ने अब साक्ष्यों के संकलन के लिए वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, आने वाले दिनों में जांच प्रक्रिया में फोरेंसिक विशेषज्ञों की भूमिका काफी बढ़ जाएगी। इसकी सहायता के लिए, गुवाहाटी में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण शुरू हो चुका है। डॉ. शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय जांच अधिकारियों को उन्नत प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा, जिससे आपराधिक जांच के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अतिरिक्त, नए आपराधिक कानूनों पर पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ कानून प्रवर्तन और जांच में सूचना प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गौरतलब है कि नए न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट भवन का निर्माण 37.8 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत से किया गया है। इस अवसर पर गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई, न्यायमूर्ति सुमन श्याम, न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराणा, विधायक कौशिक राय, दिपयान चक्रवर्ती, कमलाक्ष डे पुरकायस्थ, बिजय मालाकार, कृष्णेंदु पॉल, निहार रंगजन दास और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

एएमसीएच के छात्रावास...

चिकित्सा सहायता मांगी और फिलहाल निगरानी में हैं। एएमसीएच अधिकारियों ने कहा है कि हालांकि खाद्य विषाक्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वे स्वास्थ्य में किसी और गिरावट का आकलन करने के लिए स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि छात्रों ने पिछली रात तले हुए आलू खाए थे, जिससे बीमारी के कारण के बारे में संदेह पैदा होता है। लक्षणों के सटीक स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

16 आरक्षित वनों ...

कारण राज्य के कई हिस्सों में मानव-पशु संघर्ष बढ़ रहा है, जो चिंता का एक बड़ा कारण बन गया है। वनों पर अतिक्रमण के कारण हवा का तापमान भी बढ़ गया है और इस साल असम में सितंबर का महीना अब तक का सबसे गर्म रहा। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में 113 से अधिक अभियान चलाए गए हैं, जिसके तहत 2022-23 में 402.32 हेक्टेयर और 2023-24 में 564.58 हेक्टेयर भूमि को खाली कराया गया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि रिपोर्ट में पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। साथ ही वन संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन का संकेत भी दिया गया है। पीठ ने कहा कि खबर में यह दावा किया गया है कि कुछ जंगलों में लोग वर्षों से रह रहे हैं और उन्हें बेदखल करना मुश्किल हो सकता है। सीमाओं पर स्थित जंगलों में भी पड़ोसी राज्यों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और सीमा विवाद पूरी तरह से सुलझने के बाद ही उन्हें अतिक्रमण मुक्त किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि खबर में पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन के संबंध में *पर्याप्त मुद्दे* उठाए गए हैं और वन संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन का भी संकेत दिया गया है। न्यायाधिकरण ने राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और कामरूप महानगर जिले के जिला आयुक्त को पक्षकार या प्रतिवादी के रूप में शामिल किया। कहा कि प्रतिवादियों को न्यायाधिकरण की पूर्वी क्षेत्रीय पीठ (कोलकाता में) के समक्ष हलफनामे के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।

ढाका में कट्टरपंथियों के हमले का शिकार हुआ पश्चिम बंगाल का युवक, सुनाई आपबीती

कोलकाता (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बेलघरिया का रहने वाला 22 वर्षीय सायन घोष बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमले में घायल होकर अपने घर लौट आया है। घटना के बाद से युवक बहुत डरा हुआ है और मानसिक रूप से काफी परेशान है। सायन घोष बेलघरिया के सोनार बांग्ला इलाके का निवासी है। वह 23 नवंबर को बांग्लादेश के ढाका में अपने एक दोस्त के घर गया था। उसके पास पासपोर्ट और वीजा सहित सभी वैध दस्तावेज थे। इसी दौरान 25 नवंबर को इस्कॉन सन्यासी चिन्मयकृष्ण दास की ढाका हवाई अड्डे पर गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का विरोध प्रदर्शन और हंगामा शुरू हो गया। पीड़ित युवक के मुताबिक 26 नवंबर को, वह अपने दोस्त के घर के पास स्थित बाजार में खरीदारी करने गया था। इसी दौरान कट्टरपंथियों के एक समूह ने उसे और उसके दोस्त को घेर लिया। जब उन्हें पता चला कि सायन भारतीय नागरिक और हिंदू है, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। सायन को बुरी तरह पीटा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैसे और मोबाइल फोन भी छीन लिए गए। घटना के बाद सायन और उसके दोस्त ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उन्हें सहयोग नहीं मिला। पुलिस ने उल्टा उनसे सवाल किया कि वे बांग्लादेश क्यों आए थे। सायन के दोस्त को पुलिस ने भारतीय युवक को तुरंत अपने घर से वापस भेजने को कह दिया।

हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी के गोरचुक थाना क्षेत्र में स्पेशल टास्क फोर्स, असम (एसटीएफ) की टीम ने अभियान चलाकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने रविवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गोरचुक थाना क्षेत्र के पश्चिम बोरागांव में चलाए गए एक अभियान के दौरान दो साबुनदानी में छुपाकर रखे गए 23.43 ग्राम हेरोइन, एक मोबाइल फोन, नगद एक सौ रुपये के अलावा अन्य आपत्तिजनक सामग्री के साथ इलियास अहमद (22) को गिरफ्तार किया गया। इलियास बरपेटा का रहने वाला है। घटना के संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

भारत और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं है : महबूबा मुफ्ती

श्रीनगर। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश और भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा हाल है। हमारे जो हिंदू भाई है उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो यहां हम अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं तो फर्क क्या है? महबूबा मुफ्ती संभल हिंसा और अजमेर में मौजूद दरगाह में मंदिर के दावे को लेकर बात कर रही थी, इस बीच उन्होंने बांग्लादेश से इसको जोड़ते हुए कहा कि हमारा इतना बड़ा देश है जोकि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हम अल्पसंख्यकों को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ कर शिवलिंग ढूंढेंगे, बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहां के अत्याचार के बारे में बात करता है तो उसको जेल में डाल देंगे, यहां उमर खालिद को जेल में डाल रखा है, तो फिर फर्क क्या है, उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि भारत और बांग्लादेश में कुछ भी फर्क नहीं है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हालात अच्छे नहीं है, ऐसा है कि हमारे जो लीडर रहे हैं गांधी जी से लेकर जवाहर लाल नेहरू हो, जितने भी लीडर रहे हैं उन्होंने इस मुल्क को हिंदू, मुस्लिम, सिख , ईसाई सब का घर बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि जो यह हालात हो रहे हैं, आपस में लड़ाया जा रहा है और मुझे डर है, खौफ है कि यह जो हालात है वो 1947 में जो हालात थे यह कहीं न कहीं हमें उसी तरफ लेकर जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि जब नौजवान नौकरी की डिमांड करता है तो उनको नौकरी नहीं मिलती है, अच्छे अस्पतालों की डिमांड करते हैं लोग तो अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है। हमारी गलियां, हमारी सड़कें आप ठीक नहीं करते हो, तो आप क्या करते हो कि मस्जिद को गिरा कर इसमें मंदिर ढूंढ लो। यही हो रहा है। संभल का जिक्र करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अभी देखिए संभल में कितना बुरा हादसा हो गया है।

भारत अब लेने नहीं, बल्कि देने वाला देश है : नड्डा

इंदौर(हि.स.)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि एक समय ऐसा था, जब भारत में टिटनेस की दवा को 40 साल, टीबी की दवा को 30 साल, डिप्थीरिया की दवा को 30 साल, जापानी बुखार को ठीक करने वाली दवा आने में 100 साल लग गए, लेकिन कोरोना के दो टीके नौ माह में आ गए। जिन्होंने कई लोगों की जिंदगी बचाई। हमने चालीस देशों को मुफ्त कोरोना की दवा दी। यह बदलता भारत है। कोरोना मैनेजमेंट को उठाकर देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने कहा कि अमेरिका में स्ट्राइक हुई, यूरोप में लोगों ने लॉकडाउन लगाने से रोका, कई देश लॉकडाउन लगाने के लिए तय नहीं कर पाए। वे असमंजस में थे। लेकिन भारत में पहले जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन लगाए। भारत ने पीपीई किट बनाए, आईसीयू में जगह तैयार की, सैनेटाइजर, मास्क बनाए। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जान भी है और जहान भी। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज कोरोना वैक्सीन बनाने का अभियान भारत में चला। अब भारत लेने वाला नहीं, बल्कि देने वाला देश बन चुका है। कोरोना का मैनेजमेंट देश में प्रभावी रहा। वे रविवार को विश्व एड्स दिवस के अवसर पर इंदौर के खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एड्स को लेकर चर्चा करने में कई संकोच नहीं करना चाहिए। जब मैं इस पर बात कर सकता हूं तो आपको भी समाज में जाकर खुलकर चर्चा करना चाहिए। स्कूलों में कार्यक्रम होना चाहिए। 9वीं-10वीं के बच्चों को जागरूक करना चाहिए। कैंपेन चलाना चाहिए। हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करना चाहिए। वर्ल्ड एड्स डे एचआईवी और उसके खिलाफ चल रही जंग को डेडिकेट और रि-डेडिकेट करने का दिन है। यह दिन अपने आप को एचआईवी से प्रोटेक्ट करने का दिन है। अभी ऐसी कोई दवा नहीं आई है जो पूरी तरह एचआईवी को ठीक कर सके। दवाएं तो पूरे समय खाना पड़ेंगी, लेकिन दवाओं से व्यक्ति पूरे जीवन स्वस्थ रह सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को समाज में जगह देना चाहिए। नड्डा ने कार्यक्रम में मौजूद बच्चों से बात करते हुए कहा कि हमारे समाज ने देश में एड्स की लंबी लड़ाई लड़ी है। लेकिन हमारे नौजवानों ने अंधकार का वो काला दौर नहीं देखा। इसलिए आपको मालूम नहीं है कि एड्स का मतलब क्या है। आप लोगों ने 80 का दसक नहीं देखा। आपको मालूम नहीं है कि एड्स मतलब क्या होता है। उस समय अगर कोई एड्स मरीज किसी को छू जाए तो लोग डर जाते थे। लोग ऐसे परिवारों से दूर रहते थे। हेयर कटिंग सैलून वाला बार-बार अपने उस्तरे को पोछ्ता था तब डर लगता था। यह दौर शायद मुख्यमंत्री, सिलावट और राजेंद्र शुक्ला ने देखा है। नड्डा ने कहा कि एक समय था जब दुनिया में एड्स की दवा नहीं थी और जब दवा आई तो इतनी महंगी थी कि गरीब आदमी उन दवाओं को ले नहीं सकता था। हमारे देश की कंपनियों ने दुनिया में एड्स की सबसे सस्ती और इफेक्टिव दवाएं बनाईं।

बांग्लादेश : हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में राज्य में प्रदर्शन

श्रीभूमि (हिंस)। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के विरुद्ध श्रीभूमि जिले में विरोध-प्रदर्शन जारी है। हजारों लोग हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित *बांग्लादेश चलो* अभियान के बैनर तले निकाली गई रैली में रविवार को शामिल हुए। सुतारकांडी में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास जमकर विरोध-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई, जिसमें एक प्रदर्शनकारी घायल हो गया। यह प्रदर्शन सीमा से लगभग एक किलोमीटर दूर हुआ, जहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शित किया। भीड़ को नियंत्रित करने और आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में घुसने के प्रयास में बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रण में रखा है। *बांग्लादेश चलो* अभियान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए जवाबदेही और कार्रवाई करने की मांग की है।

तेंदुआ हुआ पिंजरे में कैद

तिनसुकिया (हिंस)। तिनसुकिया जिले के मार्घेरिटा में आतंक का पर्याय बना तेंदुआ को वन विभाग द्वारा पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग ने रविवार को बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत मिलने के बाद तेंदुआ को पकड़ने के लिए मार्घेरिटा वन कार्यालय की ओर से इलाके में एक पिंजरा लगाया गया। जिसमें तेंदुआ फंस गया। तेंदुआ को पकड़े जाने के बाद काफी संख्या में लोगों का तेंदुआ को देखने के लिए पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में और तेंदुआ है । वन विभाग की टीम बाकी बचे तेंदुआ को भी पिंजरा लगाकर जल्द से जल्द पकड़ने की स्थानीय लोगों ने अपील की है।

लखीमपुर में अभाविप के 30वें राज्य अधिवेशन की तैयारी

गुवाहाटी (हिंस)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) का 30वां राज्य अधिवेशन इस वर्ष लखीमपुर शहर के मणिकांचन कोऑर्डिनेशन ग्राउंड (एटी ग्राउंड) में आयोजित किया जाएगा। इसके मद्देनजर अधिवेशन का प्रतिक चिह्न औपचारिक रूप से जारी किया जा चुका है। महापुरुष माधवदेव के जन्मस्थान लखीमपुर में 27, 28 और 29 दिसंबर को होने वाले राज्य अधिवेशन में पूरे असम के लगभग 1200 छात्र भाग लेंगे। सम्मेलन में असम के विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति भाग लेंगे और असम और समग्र रूप से भारत से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अधिवेशन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, खुले सत्र और सांस्कृतिक जुलूस शामिल होंगे। आयोजन स्थल का नाम मणिकांचन समन्वय क्षेत्र के नाम पर रखा जाएगा, मुख्य सभागार का नाम पद्मनाथ गोहाईंबरुवा हॉल के नाम पर रखा जाएगा और मुख्य मेहराब का नाम महापुरुष माधवदेव के नाम पर रखा जाएगा। सत्र में शैक्षिक मुद्दों, सामाजिक मुद्दों और आत्मनिर्भर असम पर तीन संकल्प भी पारित रिए जाएंगे। अभाविप असम प्रदेश के राज्य सचिव हेरोल्ड मोहन ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में अधिवेशन को सफल बनाने के लिए समस्त लखीमपुर के लोगों से सहयोग की कामना की है।

महिला उत्पीड़न : महिला आयोग की टीम पहुंची धुबड़ी जेल

धुबड़ी (हिंस)। असम राज्य महिला आयोग की एक दो सदस्यीय टीम धुबड़ी जेल पहुंची। टीम में आयोग की उप निदेशक नीलिमा देवी और सदस्य परमी दास शामिल हैं। वे जिला जेल में एक महिला वार्डन के उत्पीड़न के मामले की जांच के लिए धुबड़ी पहुंचीं। आयोग की टीम ने धुबड़ी के आवर्त भवन में शीर्ष पुलिस अधिकारियों, जांच टीमों और पीड़ित महिला वार्डन के साथ बंद कमरे में अलग-अलग बैठकें कीं। महिला आयोग की उप निदेशक नीलिमा देवी ने दावा किया कि धुबड़ी जिला जेल में महिला वार्डन से बलात्कार के प्रयास के सभी सबूत और गवाह मिल गए हैं। उन्होंने धुबड़ी जिला जेल के अधीक्षक प्रशांत राजवंशी की गिरफ्तारी की भी शिफारिश की है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगी। महिला आयोग की उप निदेशक ने जेल के अंदर महिला पर शारीरिक हमले, बलात्कार के प्रयास और धमकी के बावजूद जिला जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। नीलिमा देवी ने यह भी कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जरूरत पड़ने पर महिला आयोग मुख्यमंत्री पर दबाव बनाएगा।

पांच अवैध घुसपैठियों को पुलिस ने वापस भेजा बांग्लादेश

गुवाहाटी (हिंस)। असम पुलिस ने पांच अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस बांग्लादेश भेज दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व शर्मा ने आज इस आशय की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए देते हुए कहा कि असम पुलिस ने भारत-बंगलादेश सीमा पर पांच बंगलादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया। बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान मोहम्मद नूर इस्लाम, मोहम्मद इमरान, यास्मीन अख्तर, इश्मो तारा अख्तर और मोहम्मद बाबुल हुसैन के रूप में हुई है। बाद में उन्हें वापस सीमा के दूसरी ओर भेज दिया गया। इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने असम पुलिस की सराहना की।

पोषण ले रहा है जनांदोलन का रूप : अन्नपूर्णा देवी

गुवाहाटी (हिंस)। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि पोषण अब जनांदोलन का रूप ले रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के समय में राज्य के महिला एवं बच्चों के पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकने की दिशा में वर्तमान सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी रविवार को राजधानी के दिसपुर स्थित कर भवन में एक भव्य समारोह को संबोधित कर रही थीं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अवकाश प्राप्त आंगनबाड़ी कर्मियों एवं सहायिकाओं को पेंशन के चेक वितरण की औपचारिक शुरुआत की। वहीं, मंत्री ने राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनरों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किये। कार्यक्रम में मौजूद असम की महिला एवं बाल विकास मंत्री अजंता नेओग ने कहा कि वर्तमान सरकार के समय में राज्य में बड़ी संख्या में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण की दिशा में कई कारगर कार्य किए गए हैं। वहीं, इस अवसर पर विभागीय आयुक्त सचिव मुकेश साहू ने कहा कि 97.3 फीसदी लाभार्थियों को आधार से जोड़ दिया गया है। इस दौरान उन्होंने इस दिशा में किए गए विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया। कार्यक्रम में इनके अलावा बड़ी संख्या में विभागीय पदाधिकारी, मुख्य सेविकाएं, विभागीय कर्मचारी एवं अन्य मौजूद रहे।

डिब्रूगढ़ और धुबड़ी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

गुवाहाटी (हिंस)। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 04 से 07 दिसंबर तक दोनों दिशाओं में 01-01 फेरा के लिए डिब्रूगढ़ और धुबड़ी के बीच स्पेशल ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया गया है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने रविवार को बताया कि स्पेशल ट्रेन संख्या 05938 (डिब्रूगढ़ - धुबड़ी) 4 दिसंबर, बुधवार को डिब्रूगढ़ से सुबह 07:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन धुबड़ी 02:05 बजे पहुंचेगी। वापसी दिशा में, स्पेशल ट्रेन संख्या 05937 (धुबड़ी - डिब्रूगढ़) 07 दिसंबर शनिवार को धुबड़ी से 19:20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन डिब्रूगढ़ 16:30 बजे पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन अपनी दोनों तरफ की यात्रा के दौरान अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए न्यू तिनसुकिया, नाहरकटीया, शिमलगुड़ी, फरकाटिंग, लामडिंग, गुवाहाटी, रंगिया, न्यू बंगाईगांव, फकीराग्राम, गोलकगंज होकर चलेगी। इस ट्रेन के 22 कोच में एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सीटिंग कोच उपलब्ध होंगे। कामाख्या और आनंद विहार टर्मिनल के बीच स्पेशल ट्रेन की अवधि को 06 से 29 दिसंबर तक दोनों दिशाओं में 04-04 फेरे बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। तदनुसार, प्रति शुक्रवार को चलने वाली ट्रेन संख्या 02525 (कामाख्या - आनंद विहार टर्मिनल) स्पेशल के परिचालन अवधि को 06 से 27 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। वापसी दिशा में, प्रति रविवार को चलने वाली ट्रेन संख्या 02526 (आनंद विहार टर्मिनल - कामाख्या) स्पेशल के परिचालन अवधि को 08 से 29 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। ट्रेन अपने मौजूदा समय-सारणी और ठहराव पर चलेगी और इसमें 22 कोच होंगे। एसी-फर्स्ट क्लास, एसी- 2 टियर, एसी- 3 टियर, एसी-3 टियर इकॉनोमी एवं स्लीपर क्लास और जनरल सीटिंग कोच उपलब्ध होंगे। उक्त मार्ग पर चलने वाली अन्य ट्रेनों के प्रतीक्षा सूची वाले यात्री आरामपूर्वक यात्रा करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले विवरण की जांच कर लें।

स्कॉर्पियो के साथ दो शातिर पशु चोर गिरफ्तार

कामरूप (हिंस)। कामरूप (ग्रामीण) जिले की हाजो पुलिस ने कलिताकुची इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर शातिर पशु चोर मुख्तार अली ओर उसके अन्य एक सहयोगी को स्कॉर्पियो वाहन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने रविवार को बताया कि बीते सोमवार की रात को मेहरून अली उर्फ खोरु ऑन के साथ मिलकर मुख्तार अली एक अन्य कार के जरिए कामरूप और नलबाड़ी जिले से कई मवेशियों को चुराया था। पशु चोरी मामले में व्यवहार की गई कार को घटना के दूसरे दिन मुख्तार अली के सहयोगी मेहरून अली के हाजो के सराबारी बिलपारा स्थित घर से बरामद किया था। वाहन से पुलिस दो चोरी के पशु और अन्य धारदार हथियार बरामद किया था। इस घटना में मुख्तार अली और मेहरून दोनों फरार थे। दोनों फरार पशु चोर को रविवार तड़के गुप्त सूचना के आधार हाजो पुलिस ने कलिताकुची से गिरफ्तार किया।

जोनाई में सड़क हादसे में दो बाइक सवार की मौत

धेमाजी (हिंस)। धेमाजी जिले के जोनाई में असम-अरुणाचल सीमा पर अबर लेकू में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 515 पर दो वाहनों की आमने-सामने की हुई टक्कर में दो बाइक सवारों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों बाइक चालक जोनाई बाजार से अपने घर जा रहे थे। विपरीत दिशा से आ रहे विंगर (एएस- 05 सी- 4825) से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान जोनाई के लेकू झेलम गांव के निवासी विजय उर्फ जग्गू दलै (35) और निकटवर्ती केडी चूक गांव के मोहन कुमार पेगू (40) के रूप में हुई है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश की रुकसिन पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी।

खैराबाड़ी में जनजातीय गौरव दिवस एवं स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित

रंगिया (विभास)। भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की गुवाहाटी आंचलिक के सौजन्य से तथा उदालगुड़ी जिला प्रशासन के सहयोग से खैराबारी महिरंग भवन प्रांगण में 29 नवंबर से तीन दिवसीय कार्यक्रमों के साथ आयोजित जनजातीय गौरव दिवस और स्वच्छता ही सेवा का आज समापन किया गया। जनजातीय योद्धा तथा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के मौके पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ उदालगुड़ी जिला आयुक्त पुलक पाटगिरी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इसके जनजातीय गीत-नृत्य और छात्र-छात्राओं के बीच प्रतियोगिता आयोजित हुई। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन नाटक, स्वागत समारोह, भाषण, जनजातीय लोगों की क्रिस्टी-संस्कृति, गीत, स्वच्छता, जागरूकता नाटक, भेरगांव महकमा के तहत कई स्वयं सहायता समूहों की दुकानें, सभी सरकारी विभागों के प्रतिष्ठान और दुकानें भी प्रदर्शित हुईं। कार्यक्रम के अंतर्गत खैराबारी अंचल के ज्येष्ठ पत्रकार दीपेन डेका का भी अभिनंदन किया गया। समापन समारोह में असम विधानसभा के अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन सफल रहा और जनजातीय लोग धीरे-धीरे भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष के इतिहास के बारे में जानेंगे। अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

नुमलीगढ़ में फंदे से लटककर किशोरी की मौत

गोलाघाट (हिंस)। जिले के नुमलीगढ़ ग्रामीण थाना अंतर्गत *एक नंबर पंका ग्रांट* में फंदे से लटकता हुआ एक किशोरी का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान प्रमोद सैकिया की 13 साल की लड़की के रूप में हुई है। पुलिस ने रविवार को बताया कि किशोरी अपने दादा, बड़े भाई और दो छोटे भाइयों के साथ पोंका ग्रांट में किराए के मकान में रहती थी। घर पर कोई नहीं था। इसी बीच घर पहुंचे मृतक के भाइयों ने पाया कि किशोरी घर के अंदर पर्दे का फंदा लगाकर लटक रही थी। घटना को देख दोनों छोटे भाइयों ने शोर मचाया। पड़ोस के लोग नुमलीगढ़ ग्रामीण थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। नुमलीगढ़ पुलिस पहुंची और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को नीचे उतारा और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। परिजनों को शक है कि घर में किसी के नहीं होने का फायदा उठाकर किसी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी होगी।

राज्यसभा के सांसद भुवनेश्वर कलिता ने किया आरोग्य रथ एंबुलेंस सेवा का उद्घाटन

रंगिया (विभास)। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर रंगिया महकमा सिविल अस्पताल में आरोग्य रथ नामक एक एंबुलेंस सेवा प्रारंभ की गई। जिसका आधिकारिक उद्घाटन राज्यसभा के सांसद भुवनेश्वर कलिता ने किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कामरूप जिले में अब तक चार आरोग्य रथ लॉन्च किए गए हैं। कामरूप जिले के कमलपुर, हाजो और जालुकबारी के बाद रंगिया में भी जनता की सेवा में इसका शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए बिस्तर पर पड़े मरीजों के घर में जाकर चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। और लोगों से इसके लाभ उठाने का उन्होंने आग्रह किया। उद्घाटन अस्पताल के उप-अधीक्षक डॉ. दिलीप कुमार वैश्य, चिकित्सक डॉ. त्रैलोक्य नाथ, स्वास्थ्य व सामाजिक कार्यकर्ता अमूल्य वैश्य सहित नर्सों और कर्मचारियों की उपस्थिति में किया गया जिसका संचालन मामोनी सैकिया ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में उद्घाटन कर्ता व राज्य सभा के सांसद भुवनेश्वर कलिता का अस्पताल की ओर से फुलाम गामोछा और जापी से अभिनंदन किया गया।

शिशुगांव होजाई के परिवार सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम (एफएसपी) ने *विश्व एड्स दिवस* मनाया

होजाई (निसं)। शिशुगांव (एसओएस चिल्ड्रेंस विलेज), होजाई के परिवार सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम (एफएसपी) ने रविवार को धनुहार बस्ती, हीरा बस्ती, मिलिक बस्ती और हवाईपुर सहित अपने एफएस क्लस्टरों में *विश्व एड्स दिवस* मनाया। कार्यक्रम का उद्देश्य था लोगों को एचआईवी/एड्स, इसके संचरण और निवारक उपायों के बारे में जानकारी देना। उक्त जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने हेतु एफएसपी के बाल पंचायत के बच्चों और समुदाय के सदस्यों द्वारा आयोजित सामूहिक रैली आयोजित की गई। रैली के दौरान सभी लोगों ने जागरूकता बढ़ाने हेतु हाथों में प्ले कार्ड व बैनर लेकर आगे बढ़ रहे थे। वहीं, गुवाहाटी की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था *सृष्टि* द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया, जिसमें एचआईवी के रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में एचआईवी/एड्स के रोकथाम हेतु उपलब्ध महत्वपूर्ण संसाधनों पर भी प्रकाश डाला गया, जैसे कि एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र (आईसीटीसी), रेड रिबन क्लीनिक, मुफ्त दवाइयां, परिवहन सहायता और एचआईवी से पीड़ित लोगों (पीएलडब्ल्यूएचआईवी) के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों को आगे के मार्गदर्शन के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 1097 के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम का समन्वय एफएस क्लस्टर के एनिमेटरों और ट्यूटर्स द्वारा किया गया, जिसमें चित्तरंजन मोहंती, सहायक निदेशक और निरंजन दास, एसओएस चिल्ड्रेंस विलेज होजाई के वरिष्ठ सह-कार्यकर्ता की देखरेख मैं उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल के माध्यम से, एसओएस सीवी होजाई ने समुदाय को एचआईवी/एड्स से खुद को और दूसरों को बचाने के लिए आवश्यक ज्ञान और संसाधनों के साथ सशक्त बनाने और सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

बड़े भाई की हत्या मामले में दो गिरफ्तार

शोणितपुर (हिंस)। शोणितपुर जिले के ढेकियाजुली सिडरी के दो नंबर बसासिमलू इलाके में दो छोटे भाइयों द्वारा बड़े भाई की बड़ी बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि आजगर अली नामक व्यक्ति को दो सगे छोटे भाइयों ने बड़े निर्मम तरीके से धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम मृतक का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। भाई की हत्या मामले में पुलिस ने शहर अली और महर अली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया की भूमि विवाद की वजह से दोनों भाइयों ने मिलकर बड़े भाई की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार दोनों आरोपितों से सघन पूछताछ कर रही है।

जेडी इंस्टीट्यूट गुवाहाटी ने अपने वार्षिक डिजाइन पुरस्कार 2024 में अविस्मरणीय डिजाइन उत्कृष्टता के लिए तैयार किया मंच

गुवाहाटी। लगभग दो दशकों से जेडी इंस्टीट्यूट गुवाहाटी असम में रचनात्मकता की आधारशिला रहा है, जो उत्साही शिक्षार्थियों को अग्रणी पेशेवरों में बदल रहा है। वर्ष 2006 में स्थापित, यह इस क्षेत्र में अपनी तरह का पहला मंच होने का गौरव रखता है, यह जडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थायी नींव पर बनी विरासत है, जिसकी स्थापना 1988 में श्री चंद्रकांत दलाल (अध्यक्ष) और आरसी दलाल (भारतीय फिल्म महोत्सव के विश्वव्यापी प्रबंध निदेशक और सह-संस्थापक) ने की थी। साथ मिलकर, उन्होंने एक ऐसे संस्थान की कल्पना की जो अन्वेषण, साहस और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देता है- संस्थान की प्रबंध निदेशक, सुश्री रूपल दलाल, छात्रों की उनके डिजाइन विशेषज्ञता को सामाजिक जिम्मेदारी की गहन भावना के साथ मिलाने के लिए सराहना करती हैं। सुमिता दे डेका, केंद्र निदेशक, इस बात पर जोर देती हैं कि कैसे यह आयोजन षष्ठी की स्थापना के बाद से सामने आए जबरदस्त परिवर्तनों का एक ज्वलंत प्रमाण है।

संपादकीय

खेलने की उम्र में ब्याह

इक्कीसवीं सदी के भारत में यदि हर पांच में से एक लड़की का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो जाए तो इसे विडंबना ही कहा जाएगा। पिछले एक वर्ष में दो लाख बाल विवाह कानून की सख्ती से रोके गए। निश्चित रूप से बाल विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन ही है। जिससे बच्चियां ताउम्र पढ़ाई से वंचित हो जाती हैं और उनका शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। सही मायनों में बाल विवाह कुपोषण एवं गरीबी का ऐसा चक्र पैदा करता है जिसकी कीमत राष्ट्र को चुकानी पड़ती है। चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि पश्चिम बंगाल, बिहार व त्रिपुरा में 40 फीसदी लड़कियों के विवाह 18 साल से पहले हो जाते हैं। यही वजह है कि केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। दरअसल, यह शुरुआत उन राज्यों को लेकर की गई है, जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तथ्य यह भी कि समाज में गरीबी और बाल विवाह में सीधा रिश्ता है। एक अध्ययन के अनुसार 75 फीसदी बाल विवाह गरीब परिवारों में होते हैं। जो कालांतर गरीबी के नये दुश्चक्र को जन्म देते हैं। निश्चित रूप से हमारे समाज में गरीबी व रूढ़िवाद के चलते इस कुप्रथा को बल मिलता है। अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि संपन्न, शिक्षित और प्रगतिशील समाजों में बाल विवाह के मामले सामान्यतः नजर नहीं आते। वहीं दूसरी ओर लिंगभेद की सोच भी इन विवाहों को बढ़ावा देती है। अभिभावक विषम परिस्थितियों के चलते अल्पवयस्क लड़कियों का विवाह करके जल्दी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि स्वतंत्रता से पूर्व देश में वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध कानून बनने के बावजूद इस कुप्रथा पर अंकुश क्यों नहीं लग पाया। पहले धारणा थी कि असुरक्षाबोध के चलते बाल विवाह को बढ़ावा मिलता रहा है। कम से कम स्वतंत्र भारत में बाल विवाह की सोच नहीं रहनी चाहिए थी। निस्संदेह, राजग सरकार के दौरान बाल विवाह उन्मूलन के लिये सार्थक प्रयास किए गए। हालिया बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत से पहले भी सरकार ने इस दिशा में पहल की थी। इससे पहले वर्ष 2006 में बाल विवाह कानून में सुधार किया गया। इसमें लड़कों के विवाह की उम्र 21 व लड़कियों के विवाह की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। वहीं वर्ष 2021 में राजग सरकार ने 2006 के कानून में सुधार करके लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का प्रस्ताव किया था। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट भारत में 40 फीसदी के करीब लड़कियों के 18 साल से कम उम्र में विवाह होने की बात कहती है। वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हर रोज चार हजार से अधिक बाल विवाह होने का उल्लेख करते हैं। बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में असम सरकार की सफलता का अकसर जिक्र होता है, जहां आंकड़ों में तेजी से गिरावट आई है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2029 तक बाल विवाह की दर को पांच फीसदी से नीचे लाया जाए। निस्संदेह, बाल विवाह जहां बच्चियों के मौलिक अधिकारों का हनन है, वहीं उनकी शारीरिक व मानसिक क्षमताओं को भी कमतर करता है। इससे जहां लड़कियों के अधिकारों का अतिक्रमण होता है, वहीं उनके शोषण का भी खतरा रहता है। पढ़ाई बीच में छूट जाने से उनके सपने मर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कम उम्र में शादी और बच्चे होने से उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पूरी पढ़ाई न होने तथा नौकरी न कर पाने की स्थिति में वे आर्थिक रूप से पतियों पर आश्रित हो जाती हैं। जिससे उनका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता। जिसके चलते अकसर भावनात्मक विभेद का सामना भी करना पड़ता है। बाल विवाह का होना यह भी बताता है कि हमारे समाज में अभी दहेज प्रथा का दबाव कम नहीं हुआ है। जिससे बचने के लिये अभिभावक तुरत-फुरत अल्पवयस्क लड़कियों की शादी कर देते हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी कि सिर्फ कानून बनाने से ही इस कुरीति पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, समाज में जागरूकता लाने के लिये भी राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना होगा।

> भारत में यदि हर पांच में से एक लड़की का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो जाए तो इसे विडंबना ही कहा जाएगा। पिछले एक वर्ष में दो लाख बाल विवाह कानून की सख्ती से रोके गए। निश्चित रूप से बाल विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन ही है। जिससे बच्चियां ताउम्र पढ़ाई से वंचित हो जाती हैं और उनका शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। सही मायनों में बाल विवाह कुपोषण एवं गरीबी का ऐसा चक्र पैदा करता है जिसकी कीमत राष्ट्र को चुकानी पड़ती है। चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि पश्चिम बंगाल, बिहार व त्रिपुरा में 40 फीसदी लड़कियों के विवाह 18 साल से पहले हो जाते हैं। यही वजह है कि केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। दरअसल, यह शुरुआत उन राज्यों को लेकर की गई है, जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

बढ़ता वायु प्रदूषण न केवल भारत के लिये बल्कि दुनिया के लिये एक गंभीर समस्या है

प्रदूषण से बढ़ती मौतों के लिये कौन जिम्मेदार?

ललित गर्ग

> प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों, नीतियों, और प्रदूषण को कम करने के महत्व पर ध्यान आकर्षित करना है। यह दिन भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। यह त्रासदी 2-3 दिसंबर, 1984 की रात को हुई थी। इस त्रासदी में ज़हरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन भारत में बढ़ते प्रदूषण के कारण जान और जहान दोनों ही खतरे में हैं।

प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद, प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों, नीतियों, और प्रदूषण को कम करने के महत्व पर ध्यान आकर्षित करना है। यह दिन भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। यह त्रासदी 2-3 दिसंबर, 1984 की रात को हुई थी। इस त्रासदी में ज़हरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन भारत में बढ़ते प्रदूषण के कारण जान और जहान दोनों ही खतरे में हैं। देश एवं दुनिया की हवा में घुलते प्रदूषण का 'जहर' अनेक बार खतरनाक स्थिति में पहुंच जाना चिन्ता का बड़ा कारण हैं। प्रदूषण की अनेक बंदिशों एवं हिदायतों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण की बात खोखली साबित हो रही है। यह कैसा समाज है जहां व्यक्ति के लिए पर्यावरण, अपना स्वास्थ्य या दूसरों की सुविधा-असुविधा का कोई अर्थ नहीं है। प्रदूषण के कारण जल, भूमि, और वायु प्रदूषित होता है, जिससे मौतें होती हैं, प्रदूषण से जीवन और स्वास्थ्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

जीवन-शैली ऐसी बन गयी है कि आदमी जीने के लिये सब कुछ करने लगा पर खुद जीने का अर्थ ही भूल गया, इस गंभीर होती स्थिति को यूनिसेफ और अमेरिका के स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान 'हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट' की साझेदारी में जारी रिपोर्ट ने बयां किया है, इस रिपोर्ट के आंकड़े परेशान एवं शर्मसार करने के साथ चिन्ता में डालने वाले हैं, जिसमें वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण से 21 लाख भारतीयों के मरने की बात कही गई है। ज्यादा दुख की बात यह है कि मरने वालों में 1.69 लाख बच्चे हैं, जिन्होंने अभी दुनिया ठीक से देखी ही नहीं थी। निश्चय ही ये आंकड़े जहां व्यथित, चिन्तीत व परेशान करने वाले हैं। वहीं सरकार के नीति-नियंताओं के लिये यह शर्म का विषय होना चाहिए, लेकिन उन्हें शर्म आती ही कहा है? तनिक भी शर्म आती तो सरकारें एवं उनके कर्ता-धर्मा इस दिशा में गंभीर प्रयास करते। सरकार की नाकामयियों ही हैं कि जिन्दगी विषमताओं और विसंगतियों से घिरी होकर उसे कहीं से रोशनी की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। बढ़ता वायु प्रदूषण न केवल भारत के लिये बल्कि दुनिया के लिये एक गंभीर समस्या है। चीन में भी इसी कालखंड में 23 लाख लोग वायु प्रदूषण से मरे हैं। जहां तक पूरी दुनिया में इस वर्ष मरने वालों की कुल संख्या का प्रश्न है तो यह करीब 81 लाख बतायी

जाती है। चिंता की बात यह है कि भारत व चीन में वायु प्रदूषण से मरने वालों की कुल संख्या के मामले में यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 54 फीसदी है। जो हमारे तंत्र की विफलता, गरीबी और प्रदूषण नियंत्रण में शासन-प्रशासन की कोताही एवं लापरवाही को ही दर्शाता है। इसमें आम आदमी की लापरवाही भी कम नहीं है। आम आदमी को पता ही नहीं होता है कि किन प्रमुख कारणों से यह प्रदूषण फैल रहा है और किस तरह वे इससे बचाव कर सकते हैं। प्रश्न है कि आम आदमी एवं उसकी जीवनशैली वायु प्रदूषण को इतना बेपरवाह होकर क्यों फैलाती है? क्यों आदमी मृत्यु से नहीं डर रहा है? क्यों भयभीत नहीं है? देश की जनता दुख, दर्द और संवेदनहीनता के जटिल दौर से रूबरू है, प्रदूषण जैसी समस्याएं नये-नये मुखौटे ओढ़कर डराती है, भयभीत करती है। विडम्बना तो यह है कि विभिन्न राज्यों की सरकारें इस विकट होती समस्या का हल निकालने की बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप करती है, जानबूझकर प्रदूषण फैलाती है ताकि एक-दूसरे की छीछालेदर कर सके।

दिल्ली सहित उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्थिति में बना रहता है। हालत ये बनते हैं कि कभी-कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता है और लोगों को घरों में ही रहने को मजबूर होना पड़ता है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में प्रदूषण का बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआं होता है। पराली के बाद पटाखों का धुआं भी बड़ी समस्या है, इसके अलावा सड़कों पर लगातार बढ़ते निजी वाहन, गुणवत्ता के ईंधन का उपयोग न होना, निर्माण कार्य खुले में होना, उद्योगों की घातक गैसों व धुएं का नियमन न होने जैसे अनेक कारण वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर आवासीय कॉलोनियों व व्यावसायिक संस्थानों का विज्ञानसम्मत ढंग से निर्माण न हो पाना भी प्रदूषण बढ़ाने की एक वजह है। यह कैसी शासन-व्यवस्था है? यह कैसा अदालतों की अवमानना का मामला है? यह सभ्यता की निचली सीढ़ी है, जहां तनाव-ठहराव की स्थितियों के बीच हर व्यक्ति, शासन-प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण के अपने दायित्वों से दूर होता जा रहा है।

यूनीसेफ की रिपोर्ट में वायु प्रदूषण से 1 लाख 69 हजार बच्चे जिनकी औसत आयु पांच साल से कम बतायी गई है, मौत के शिकार होते हैं। जानलेवा प्रदूषण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर होने से बच्चे समय से पहले जन्म ले लेते हैं, इनका समुचित शारीरिक विकास सही ढ़ंग से नहीं हो पाता। इससे बच्चों का कम वजन का पैदा होना, अस्थमा तथा फेफड़ों की बीमारियां से पीड़ति होना हैं। हमारे लिये चिंता की बात यह है कि बेहद गरीब मुल्कों नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इथोपिया से ज्यादा बच्चे हमारे देश में वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। विडंबना यह है कि ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के संकट ने वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या को बढ़ाया ही है। एक अरब चालीस करोड़ जनसंख्या वाले देश भारत के लिये यह संकट बहुत बड़ा है। दिल्ली सहित देश के कई महानगरों में प्रदूषण जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गयी है।

हर कुछ समय बाद अलग-अलग वजहों से हवा की गुणवत्ता का स्तर 'बेहद खराब' की श्रेणी में दर्ज किया जाता है और सरकार की ओर से इस स्थिति में सुधार के लिए कई तरह के उपाय करने की घोषणा की जाती है। हो सकता है कि ऐसा होता भी हो, लेकिन सच यह है कि फिर कुछ समय बाद प्रदूषण का स्तर गहराने के साथ यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसकी असली जड़ क्या है और क्या सरकार की कोशिशें सही दिशा में हो पा रही है? इस विकट समस्या से मुक्ति के लिये ठोस कदम उठाने होंगे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहर वायु प्रदूषण की गंभीर मार झेलते हैं। इसका पता तब ज्यादा चलता है जब वैश्विक पर्यावरण संस्थान अपने वायु प्रदूषण सूचकांक में शहरों की स्थिति को बताते हैं। पिछले कई सालों से दुनिया के पहले बीस प्रदूषित शहरों में भारत के कई शहर दर्ज होते रहे हैं। जाहिर है, हम वायु प्रदूषण के दिनोंदिन गहराते संकट से निपट पाने में तो कामयाब हो नहीं पा रहे, बल्कि जानते-बूझते ऐसे काम करने में जरा नहीं हिचकिचा रहे जो हवा को जहरीला बना रहे हैं। चिंता की बात यह है कि मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण ही है।

दृष्टि कोण

व्यवस्था में पारदर्शिता से दूर होगा कुपोषण

हाल ही में इंडियन कौंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनामिक रिलेशंस द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में पाया गया है कि देश पीडीएस के तहत भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा आपूर्ति किए गए अनाज का 28 फीसदी इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। यानी सालाना करीब दो करोड़ टन अनाज का लीकेज होता है। अर्थव्यवस्था को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस वजह से सालाना करीब 69 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का आर्थिक नुकसान होता है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल 2.05 लाख करोड़ रुपये का है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2016 से राशन की दुकानों में पाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों की शुरुआत से लीकेज में कमी आई है। वर्ष 2011-12 की खपत संख्या के आधार पर शांता कुमार समिति ने कहा था कि पीडीएस व्यवस्था में करीब 46 फीसदी लीकेज है। यद्यपि इस समय इस लीकेज में कमी आई है, लेकिन यह अभी भी काफी अधिक है। ऐसे में जरूरी है कि पीडीएस के लिए बेहतर निगरानी और संरचनात्मक सुधारों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ा जाए। देश में गरीबों पर केंद्रित लक्षित पीडीएस की शुरुआत जून, 1997 में हुई है। इस समय दुनिया में भारत सबसे बड़ी सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के लिए जाना जाता है। देश भर में मौजूदा पांच लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाता है। खासतौर से सितंबर, 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के पारित होने के साथ ही पीडीएस व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। यह अधिनियम देश की 67 फीसदी आबादी को अपने दायरे में लेता है। सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान वंचित वर्गों के पात्र लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त अनाज दिया जाने लगा है और तब से लगातार अब तक केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत देश के 81.35 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न मुहैया करा रही है। सरकार ने वर्ष 2028 तक इस योजना का लाभ सुनिश्चित किया है। देश में कमजोर वर्ग के लोगों को व्यवस्थित रूप से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किए जाने में पीडीएस की अहम भूमिका है। इससे गरीबी में कमी आ रही है। कई प्रमुख वैश्विक संगठनों के द्वारा उनकी रिपोर्टों में भारत में बहुआयामी गरीबी घटाने में 81 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त खाद्यान्न दिए जाने और उससे गरीब वर्ग की उत्पादकता बढ़ने के निष्कर्ष भी दिए गए हैं। अमेरिकी के प्रसिद्ध थिंक टैंक द ब्रुकिंग्स इंस्टिट्यूशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां वर्ष 2011-12 में भारत की 12.2 फीसदी आबादी अत्यधिक गरीब थी, वहीं यह वर्ष 2022-23 में घटकर महज दो फीसदी ही रह गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबों की उत्पादकता वृद्धि, तेज विकास और असमानता में कमी के चलते भारत को यह कामयाबी मिली है। लेकिन अभी भी कमजोर वर्ग तक निःशुल्क गेहूं और चावल के अलावा पोषण युक्त श्रीअन्न यानी मिलेट्स की उपयुक्त आपूर्ति न होने से करोड़ों लोग पोषण सुरक्षा के मद्देनजर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) 2024 में भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर है। लेकिन भारत के लिए अभी भी हंगर इंडेक्स का स्कोर 27.3 है जो गंभीर बना हुआ है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा जारी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत में करीब 74 फीसदी लोगों को पोषण युक्त आहार नहीं मिल पाता है। निश्चित रूप से देश के 81 करोड़ से अधिक लोगों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण, इच्छित लाभार्थियों तक इसकी उपयुक्त पहुंच और पोषण युक्त खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मद्देनजर देश की पीडीएस व्यवस्था पर नए सिरे से विचार करना होगा।

कुछ अलग

ज़हरीली प्राणवायु

राजधानी दिल्ली व एनसीआर में अनियंत्रित वायु प्रदूषण को लेकर देश की शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार व पुलिस को फिर फटकार लगायी है। कोर्ट ने नाराजगी जतायी कि वायु गुणवत्ता की बेहद गंभीर स्थिति होने पर सुधार हेतु ग्रैप-4 लागू करने में कोताही बरती जा रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार व पुलिस को आड़े हाथों लिया कि क्यों रोक के बावजूद दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश जारी है। कोर्ट ने दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश की निगरानी को तेरह वकीलों को नियुक्त किया, जो सोमवार को अपनी रिपोर्ट देंगे। कोर्ट ने दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हरियाणा व उत्तर प्रदेश सरकारों को सख्ती से ग्रैप-4 की व्यवस्था लागू करने को कहा। अदालत का कहना था कि सभी राज्यों का दायित्व है कि नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए। दरअसल, न्यायमूर्ति अभय एस.ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ग्रैप-4 व्यवस्था लागू करने की खामियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है। अदालत ने केंद्र सरकार से दिल्ली में प्रवेश के 113 स्थानों पर निगरानी के लिये पुलिस कर्मियों की तैनाती को कहा, इनमें प्रवेश के तेरह मार्ग ट्रकों के लिये हैं। दरअसल, अदालत ने दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले राज्य हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश सरकारों को 18 नवंबर को निर्देश दिया था कि ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंधों के क्रियान्वयन के लिये तुरंत टीम गठित की जाए। कोर्ट ने सख्ती से पाबंदियां लागू न किये जाने पर नाराजगी जतायी। उल्लेखनीय है कि इस सप्ताह की शुरुआत में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई के गंभीर से अधिक के स्तर पर पहुंचने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-4 लागू किया गया था। जिसके अंतर्गत ट्रकों व भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश व सार्वजनिक निर्माण पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। प्रश्न है कि क्यों हमारी सरकार जन-स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में तब तक सोयी रहती है, जब तक कि पानी सिर के ऊपर से न गुजरने लगे। क्यों हर साल शीर्ष अदालत को सरकार, पुलिस व पर्यावरण संरक्षण हेतु बनी संस्थाओं को नींद से जगाना पड़ता है? क्यों अदालत पहले आदेश दे और फिर उसके क्रियान्वयन की निगरानी करे? क्यों सरकारें आग लगने पर कुंआ खोदने की फितरत से बाज नहीं आती। अदालत ने कहा कि हर नागरिक को स्वच्छ हवा देना सरकारों का दायित्व है तो क्या सरकारें जिम्मेदारी निभा रही हैं? सर्दी की दस्तक देते ही हर साल अक्तूबर-नवंबर में प्रदूषण संकट पैदा होता है, फिर भी सारे साल प्रदूषण को काबू करने के उपया क्यों नहीं किए जाते? क्यों प्रदूषण संकट गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद सरकारें हाथ-पैर मारना शुरू करती हैं? कल्पना कीजिए श्वसनतंत्र व दमा जैसे रोगों से ग्रस्त लोग इस भयावह प्रदूषण संकट से कैसे जूझ रहे होंगे? विडंबना ही कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे परिवेश-पर्यावरण छोड़ेंगे। सवाल हवा का ही नहीं, पानी पर भी बड़ा संकट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने नासा व जर्मनी के उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर चिंता बढ़ाने वाला खुलासा किया कि वर्ष 2014 के बाद से स्वच्छ जल के स्तर पर अप्रत्याशित गिरावट देखी गई है। निश्चित रूप से इस स्थिति के लिये हम सब सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। पानी के अंधाधुंध उपयोग, वन क्षेत्रफल का संकुचन और इंसान की अंतहीन लिप्साओं व वाहनों के दबाव ने धरती का जैसे तापमान बढ़ाया है, उसने पानी की वाष्पन की गति तेज कर दी है।

देश दुनीया से

जलवायु संरक्षण की आधी-अधूरी कोशिशें

बाकू में संपन्न जलवायु वार्ता का नवीनतम दौर (कॉप-29) एक विवादित समझौते के साथ समाप्त हुआ। उम्मीद थी कि इसमें मुख्य विषय जलवायु सुधार के वास्ते वित्तीय प्रबंधन पर केंद्रित रहेगा। यह संदर्भ स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण को लेकर है ताकि जलवायु परिवर्तनों पर लगाम लग पाए और सुधार कार्य अपनाए जाएं। दशकों से, विकासशील देश जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में प्रभावी उपाय करने के वास्ते अतिरिक्त धन की मांग करते आए हैं। विकासशील देश चाहते हैं कि अमीर देश अधिक जिम्मेदारी उठाएं क्योंकि वर्तमान संकट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार वही हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से उत्तरी गोलार्ध के देशों से हुआ ऐतिहासिक उत्सर्जन ही जलवायु संकट का कारण बना है। जलवायु परिवर्तन सुधार फंड की मात्रा और इसका स्रोत लंबे समय से विकसित और विकासशील देशों के बीच विवाद का विषय रहा है। इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में, बाकू वार्ता में एक अच्छा समझौता बनने की आशा जगी थी। वार्ता के निष्कर्ष में, विकासशील देशों को हर साल जलवायु सुधार के लिए, 2035 तक, कम-से-कम 300 बिलियन डॉलर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह धन विभिन्न स्रोतों से आएगा- इसमें सार्वजनिक, निजी, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और वैकल्पिक स्रोत भी शामिल हैं। इस वित्तपोषण को उपलब्ध कराने में विकसित देश अग्रणी भूमिका निभाएंगे और विकासशील देशों को स्वेच्छा से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। किंतु बाकू में निर्धारित वित्त लक्ष्य विकासशील देशों द्वारा मांगे गए धन और समय-सीमा से बहुत कम है- 2025 से विकसित देशों द्वारा हर साल इस मद में 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाए जाने हैं। किंतु, न केवल यह आंकड़ा मांगी गई मात्रा से बहुत कम है बल्कि समय-सीमा भी बहुत दूर है। अब यह पैंतरा उत्तरी गोलार्ध मुल्कों की एक जानी-पहचानी रणनीति बन चुकी है कि किसी भी तत्काल प्रतिबद्धता से बचने के लिए एक कमजोर लक्ष्य और बहुत लंबी समय-सीमा तय कर देना। इसके अलावा, जिस वित्तपोषण का वादा किया गया है वह केवल अमीर मुल्कों से नहीं आएगा। विकासशील देशों को भी इसमें योगदान देना होगा। जाहिर है, इस प्रावधान ने विकासशील देशों को परेशान कर डाला है। वार्ता के अंत में, भारत, बोलीविया और नाइजीरिया ने इस लचर संधि पर अपनी चिंता व्यक्त की, जिसे आधिकारिक तौर पर 'जलवायु वित्त हेतु नवीन सामूहिक मात्रा निर्धारण लक्ष्य' का नाम दिया गया है। भारत ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप) के अध्यक्ष पर संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में निहित बहुपक्षीय वार्ता के मानदंडों का पालन किए बिना समझौते को आगे बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी की जरूरत है। इसके शमन के लिए धन की आवश्यकता है- उत्सर्जन को महत्वपूर्ण रूप से कम करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। यानी अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं, ऊर्जा दक्षता, जीवित प्राकृतिक संसाधन और भूमि उपयोग का प्रबंधन, थलीय और जलीय जैव विविधता की सुरक्षा, स्वच्छ परिवहन आदि का इंतजाम करने वास्ते धन उपलब्धता। अतिरिक्त धन की दूसरी प्रमुख आवश्यकता अनुकूलन करने के वास्ते है- प्रतिकूल प्रभावों को अनुकूल बनाना और बदलती जलवायु के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना। उदाहरण के लिए, इसमें शामिल हैं : तूफान और बाढ़ का सामना करने लायक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन की जरूरत, वर्तमान बुनियादी ढांचा ऊपर उठते समुद्र तल से दूर स्थानांतरित करना, सूखे का सामना करने लायक फसलों के बीज विकसित करना और इनका वितरण। इसके अलावा, 'हानि एवं नुकसान' नामक तीसरी कार्रवाई के लिए धन की आवश्यकता है ताकि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में देशों को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। पिछले कुछ वर्षों में, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के तहत जलवायु वित्त के लिए अनेकानेक तंत्र और कोष बनाए गए हैं। इनमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा, हरित जलवायु कोष, विशेष जलवायु परिवर्तन कोष, अल्प विकसित देशों का कोष, अनुकूलन कोष आदि शामिल हैं। हालांकि, हकीकत यह है कि विकासशील देशों को उपलब्ध करवाई जाने वाली इन निधियों में धन की आमद बहुत कम रही है। उदाहरणार्थ, ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 2020-23 की अवधि के दौरान 129 विकासशील देशों में 243 परियोजनाओं के वास्ते कुल 13.5 बिलियन डॉलर देना मंजूर किया। अनुकूलन कोष ने 2010 से कई विकासशील देशों में 183 अनुकूलन परियोजनाओं के लिए 1.2 बिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई थी। वहीं अन्य तंत्रों से धन का प्रवाह और भी कम है। कुल मिलाकर, यूएनएफसीसीसी द्वारा प्रवर्तित निधियों और अन्य तंत्रों से उपलब्ध वित्त की मात्रा आवश्यकता से बहुत कम है। इसलिए, बाकू में मांग धन की मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता बढ़ाने की भी थी। लेकिन, धनी पश्चिमी देशों ने वित्तीय लक्ष्य को न्यूनतम रखने और समय सीमा यथासंभव लंबा खींचने के वास्ते हर संभव प्रयास किए। नए और अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए प्रतिबद्धता बनाने की बजाय, मौजूदा विकास सहायता को जलवायु वित्तपोषण का ठप्पा लगाकर, नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह होने पर, बहुपक्षीय वित्तपोषण और विकास वित्तपोषण को जलवायु सहायता के रूप में गिना जाएगा। अब, निजी निवेश के अलावा विकास-बैंक ऋण और सरकारी खर्च द्वारा 'जुटाए गए' निजी वित्त भी बृहद जलवायु वित्त के अंतर्गत आएंगे। इन सबने विकासशील देशों को मिलने वाली मौजूदा विकास सहायता के अलावा मुख्य रूप से सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त वित्तपोषण की गुणवत्ता को भी कमजोर कर डाला है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की वापसी और उनके जलवायु विरोधी रुख के हौवे से लाभ उठाते हुए, विकसित देशों ने कमजोर वित्तीय समझौते को आगे बढ़ाया। उन्होंने डर बनाया कि यदि अमेरिका बहुपक्षीय जलवायु ढांचे से बाहर निकल गया, जैसा कि ट्रम्प ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान किया था, तो इसके असर से यूएनएफसीसीसी पटरी से उतर सकता है। संयुक्त राष्ट्र प्रक्रिया के तहत, अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान सहित 24 विकसित देशों को विकासशील मुल्कों को जलवायु वित्त प्रदान करना है। यदि ट्रम्प के नेतृत्व वाला अमेरिका जलवायु प्रक्रिया से हट जाता है, तो अन्य विकसित देशों को अधिक बोझ उठाना पड़ेगा।

आप का नजरीया

कट्टरता का बांग्लादेश

बांग्लादेश में हसीना सरकार के पतन और उनके भारत में शरण लेने के बाद अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर जिस तरह लगातार हमले हो रहे हैं, इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी उसकी अगली कड़ी है। दास की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके वकील की निर्मम हत्या असहिष्णुता की पराकाष्ठा को ही दर्शाती है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि वहां अल्पसंख्यक किन भयावह स्थितियों का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे लोगों पर हमले तक किए गए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के पैरोकार दास को कथित रूप से बांग्लादेशी झंडे का अपमान करने तथा राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने के कारण बांग्लादेश और सीमा पार भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। दरअसल, इस अशांति का संदर्भ लगातार अल्पसंख्यक उत्पीड़न के पैटर्न में निहित हैं। बांग्लादेश के संवैधानिक आश्वासन के बावजूद वहां के हिंदू, जो कि आबादी का लगभग नौ फीसदी हैं, लगातार हिंसा, बर्बरता और सामाजिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। वहां हिंदुओं के घरों व मंदिरों पर भीड़ पर हमलों की खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। जिसमें हसीना सरकार के पतन के बाद खासी तेजी आई है। आधिकारिक रूप से इस्लामिक धर्म वाले इस देश में यह स्थिति अल्पसंख्यकों की व्यापक असुरक्षा को दर्शाती है। अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा सुरक्षा की गुहार लगाये जाने के बाद विश्वास बहाली की जिम्मेदारी कार्यवाहक सरकार पर है। जिसका दायित्व बनता है कि उत्पीड़न के शिकार लोगों को न्याय दिलाने के लिये विशेष न्यायाधिकरण के जरिये यथाशीघ्र कार्रवाई करे। यदि समय रहते ऐसा नहीं होता तो अशांति के बढ़ने का खतरा बना रहेगा। मौजूदा घटनाचक्र से बांग्लादेश की प्रगतिशील लोकतंत्र की छवि कमजोर हुई है। निस्संदेह, वहां सभी अल्पसंख्यकों के लिये शांति और सुरक्षा एक जीवंत वास्तविकता होनी चाहिए। ढाका सरकार को छात्र आंदोलन के जरिये हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद पनप रही कट्टरता पर अंकुश लगाना चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लगातार उत्पीड़न के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं गाहे-बगाहे आती रही हैं। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर गंभीर चिंता जतायी थी। यहां तक कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों पर बढ़े हमलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट में हसीना सरकार के पतन के बाद के एक पखवाड़े में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के दो हजार से अधिक मामलों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट इस बात पर भी चिंता जताती है कि ऐसे मामलों में अपराधियों की पहचान होने के बावजूद उन्हें दंडित नहीं किया गया। बल्कि इसके बहाने राजनीतिक विरोधियों को ही निशाना बनाया गया। ऐसी हिंसा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी तल्ख प्रतिक्रिया दर्ज की गई है।

जबरन किसी का धर्मांतरण न हो, ऐसा कानून होना ही चाहिए : मंत्री शेखावत

जोधपुर (हिंस)। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार के लाए जा रहे धर्मांतरण कानून का स्वागत किया है। शेखावत ने कहा कि जबरन किसी का भी धर्मांतरण न हो, निश्चित रूप से ऐसा कानून होना ही चाहिए। हम सब लोग राजस्थान सरकार के इस निर्णय के साथ हैं। रविवार को गृह जिले पहुंचे शेखावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रलोभन के आधार पर और जबरन धर्मांतरण न हो, राजस्थान में इस तरह का कानून राज्य सरकार लेकर आ रही है, मैं उसका स्वागत करता हूं। कांग्रेस के ईवीएम पर उंगली उठाने के सवालों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड और जिन सीटों पर वो जीते हैं, पहले उसका स्पष्टीकरण दे दें। यह सब खिसियानी बिल्ली खंभा नोंचे जैसी स्थिति है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और मैंने भी मतगणना से पहले कहा था कि परिणाम के दिन शाम तक ईवीएम बदनाम हो जाएगी। ईवीएम को बदनामी मिल रही है। आने वाले समय में वो जब चुनाव हारेंगे, तब

ईवीएम को इसी तरह से कोसेंगे। राजस्थान में उप चुनाव के परिणाम को लेकर शेखावत ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम एक से अनेक होने वाले हैं। कांग्रेस, उसकी विचारधारा, नेतृत्व को देश-प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। यह विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग हैं। इनकी चाल, चरित्र और चेहरे बेनकाब हो गए हैं। राजस्थान और देश की जनता इनको कभी अवसर नहीं देगी। प्रयागराज में जनवरी-फरवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ पर शेखावत ने कहा कि महाकुंभ दुनिया का मनुष्यों का सबसे बड़ा समागम है। भारत की वर्ल्ड हेरिटेज इनटेंजिबल ऐसेट है। विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा कई बार विचार-विर्मश हुआ है। इस तरह की अपेक्षा है कि महाकुंभ में 45 दिन में 45 करोड़ लोग आएंगे। हर आने वाले व्यक्ति के कम्युनिकेशन, कम्प्यूटेशन, सेनिटेशन और उसका एक्सपीरियंस, इन चारों चीजों को लेकर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और दुनिया के अलग-अलग कोनों से आने वाले पर्यटकों को पूरे भारत का दर्शन एक स्थान पर हो, इसको लेकर संस्कृति मंत्रालय ने बड़ी योजना का निर्माण किया है। उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस की बधाई देते हुए शेखावत ने कहा कि जिनेवा कन्वेंशन के आधार पर तय हुआ था कि सेना बॉर्डर से पीछे रहेगी। उसी के अनुरूप भारत में सीमा प्रहरियों के रूप में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का गठन हुआ। अटल जी के समय में निर्णय हुआ कि एक फोर्स, एक सीमा की रक्षा करे, तब से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल देश के सबसे बड़े केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के रूप में काम कर रही है। अपने नाम के अनुरूप सीमाओं की रक्षा ही नहीं, सुरक्षा कर भी बीएसएफ ने अद्भुत काम किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पूरे विश्व भर में एकमात्र केंद्रीय रिर्जव पुलिस है, जिसके पास में जल, थल और नभ, तीनों पर काम करने की जिम्मेदारी भी है, क्षमता भी है और अनुभव भी है। शेखावत ने कहा कि बीएसएफ ने 1971 की लड़ाई में, कारगिल की लड़ाई में, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया है। मैं सुरक्षा बल के सब जवानों से लेकर उनके महानिदेशक को बधाई देता हूं और हम सब लोग ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक नई जिम्मेदारी के एहसास के साथ में आगे बढ़े, ऐसी कामना है।

अधिकारी अगर ज्यादा परेशान करे तो ठोक लिया करो, फिर हम निपट लेंगे : विधायक पूनियां

जयपुर (हिंस)। राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और संगरिया (हनुमानगढ़) से विधायक अभिमन्यु पूनियां ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अधिकारी अगर ज्यादा परेशान करे तो नौजवान मजबूत है, अधिकारी को ठोक लिया करो। फिर हम निपट लेंगे। पूनियां शनिवार को प्रदेश यूथ कांग्रेस की सेड़वा (बाड़मेर) में हुई जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के किसी साथी या आम जनता के साथ अन्याय हुआ तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लेकर हर जगह जाएगा। तहसील, उपखंड, जिला स्तर और आईजी का भी घेराव करना पड़े तो पीछे नहीं हटेगा। जनसभा से पहले नौकरी दो-नशा नहीं अभियान के तहत धनाऊ से सेड़वा तक बाइक रैली भी निकाली गई। यूथ कांग्रेस की 19 किलोमीटर की बाइक रैली में बाड़मेर सहित आसपास के भी कई जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। पूनियां ने सभा में कहा कि हम लोग आपके साथ हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, मारवाड़ का नौजवान वैसे ही मजबूत है। अधिकारी को ठोक (पीट) लिया करो। उसके बाद उम्मेदाराम (बाड़मेर सांसद) और हम सब निपट लेंगे। राजस्थान में नशा बढ़ रहा है। नशे की वजह से पूरे गांव का माहौल खराब होता है। एक व्यक्ति का नशा परिवार को नहीं बल्कि कई परिवारों को खराब करता है। मैं जिस इलाके से आता हूं वहां देखेंगे तो पूरा सफेद पाउडर से खत्म हो चुका है। सरकारें नौजवान की बात करती हैं। रोजगार की बात करती हैं। देश में जब से मोदी सरकार

आई है तब से रोजगार देने की केवल बात की है, एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया। पूनियां ने कहा कि राजस्थान में सरकार का एक साल पूरा हो गया। एक भी युवा को नौकरी नहीं दी। कांग्रेस की मजबूती आप हैं। आप नौजवान साथी हैं। बाइक रैली से सरकार और जिला प्रशासन को संदेश दिया है। आपको (सरकार-प्रशासन) नौजवानों की बात सुननी पड़ेगी। पानी, बिजली पर बात करनी पड़ेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछिए कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं। जोधपुर में एक माह में 10-10 बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। राजस्थान सरकार सो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कहा था कि सत्ता में आए तो पेपर लीक करने वालों को जेल करा देंगे। पेपर रद्द करवा देंगे। एक साल हो गया। सरकार सिर्फ नौजवान साथियों को पकड़ रही है। जनसभा में सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने भी राजस्थान सरकार पर सियासी हमला बोला।

देशभर में आठ ठगों ने 74 करोड़ रुपए की ठगी को दिया अंजाम, सभी गिरफ्तार

गुरुग्राम (हिंस)। गुरुग्राम के साईबर अपराध पुलिस थानों की पुलिस टीमों द्वारा आठ साईबर ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। सहायक पुलिस आयुक्त साईबर अपराध प्रियांशु दिवान के नेतृत्व में ठगी की 7427 वारदातों का खुलासा पुलिस ने किया। साईबर ठगी के आरोपी जकरिया खान पुत्र इस्लाम निवासी फिरोजपुर जिला नूंह को थाना साईबर अपराध दक्षिण में गिरफ्तार किया गया। साईबर ठग नरेश कुमार निवासी नेहरू नगर डीडवाना राजस्थान को पुलिस थाना साईबर अपराध दक्षिण ने काबू किया। सुनील कुमार निवासी अशोक विहार गुरुग्राम को पुलिस थाना साईबर पूर्व में काबू किया गया। लक्ष्य, अमृतपाल व चेतन को पुलिस थाना साईबर पूर्व ने गिरफ्तार किया। कनिष्क प्रताप निवासी मोडाखेड़ा जिला हिसार को पुलिस थाना साईबर पूर्व की ओर से गिरफ्तार किया गया। अमित कुमार निवासी राजनगर जिला जींद को थाना साईबर पश्चिम में काबू किया गया। गुरुग्राम पुलिस द्वारा ठगी के इन आरोपियों के कब्जा से बरामद किए सात मोबाईल फोन व एक सिम कार्ड का इंडियन साईबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर से डाटा जांच कराने पर ठगी की वारदातों का खुलासा हुआ। आरोपियों के खिलाफ देशभर में लगभग 74 करोड़ 20 लाख रुपयों की ठगी करने के संबंध में 7427 शिकायतें और 292 केस दर्ज हैं। इनमें से 24 केस हरियाणा में दर्ज हैं। थाना स ईबर अपराध पूर्व गुरुग्राम में 4 केस व दक्षिण में दो केस दर्ज हैं। गुरुग्राम पुलिस द्वारा की जांच में यह सामने आया कि आरोपी इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड, टास्क बेस्ड फ्रॉड व्हाट्सएप पर फोटो लगाकर, फेसबुक पर जानकार बनकर व यूपीआई के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देकर ठगी करते थे।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हरियाणा के अंदर अलग से वर्गीकरण की उठी मांग

जींद (हिंस)। इक्नोमिक विक्कर सैक्शन यानि (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण में हरियाणा के अंदर अलग से वर्गीकरण की जो मांग पिछले कुछ माह से उठ रही थी, उसको रविवार के दिन जींद की धरा पर सत्ता के सारथी मिलते हुए दिखाई दिए। जींद शहर के भिवानी बाईपास चौक के नजदीक विकास नगर में स्थित भाई सुरेंद्र कुमार मैमोरियल नर्सिंग कॉलेज के परिसर में आयोजित अभिनंदन एवं स्वागत समारोह में उमड़ी भीड़ के बीच मुख्यातिथि के तौर पर पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, सहकारिता एवं जेल मंत्री डा. अरविंद शर्मा, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि जरूरतमंदों के हितो के लिए आज जो आवाज पुरजोर तरीके से बुलंद हुई है, उसे पूरी शिद्दत के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी के समक्ष पैरवी कर सिरे चढ़ाने का काम करेगें। जिसका जो हक है, उसे देने में मुख्यमंत्री नायब सैनी का कोई जवाब नहीं है। हरियाणा के सहकारिता एवं जेल मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बतौर मुख्य वक्ता ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक उनकी रगो में खून है, तब तक वे समाज के हित में हमेशा ही मैदान में खड़े मिलेगें। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज 36 वर्ग को साथ लेकर चलता है। इसलिए ब्राह्मणों को हर जगह मान-सम्मान मिलता है। उन्होंने समारोह

में उमड़ी हजारो की भीड़ को आश्वस्त किया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिलाने के लिए कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समक्ष कड़ी पैरवी की थी। उस दौरान मैंने कहा था कि सामान्य जाति में जो गरीब है, उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। उसके बाद सरकार ने मंथन किया और ईबीपीजी आरक्षण दिया। आरक्षण देने के दौरान जो कमी रह गई थी, उसके नतीजन वह आगे चलकर बैन हो गया। किं तु हरियाणा में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी सबको हक देने में विश्वास रखते है। इसलिए पूरा विश्वास है कि आज हजारो लोगों ने एक साथ जो आवाज बुलंद की है, उसको मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर बल देते हुए सिरे चढ़ाने का काम करेगें। सहकारिता मंत्री ने कहा कि हरियाणा ही नहीं पूरे देश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए। इससे मंदिर के पुजारियों को निश्चित तौर पर बड़ी राहत मिलेगी। भाजपा सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है, जो निकट भविष्य में फलीभूत होता हुआ नजर आएगा। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिढ़ा ने कहा कि ब्राह्मण समाज का पूजा-पाठ में विशेष सहयोग रहता है। इसलिए ब्राह्मण समाज का बच्चा भी पूजनीय माना जाता है। आज हजारो प्रबुद्ध लोगों के बीच विश्वास दिलाता हूं कि जो मांगे ज्ञापन के मार्फत रखी गई है, उनको मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर सिरे चढ़ाने का कार्य करूंगा। डॉ. कृष्ण मिढ़ा ने कहा कि भगवान परशुराम का चौक हो या फिर ब्राह्मण धर्मशाला को लेकर जब भी समाज ने सहयोग मांगा, तभी प्रयास किया कि हर संभंव सहायता करूं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदैव मेरी पैरवी को सम्मान देने का कार्य किया है। जींद के हित के लिए मैडिकल कॉलेज और भाखड़ा का नीला पानी लाने के लिए जो कदम आगे बढ़ाया, उसे भाजपा सरकार ने मजबूती देने का कार्य किया। इसलिए समारोह में उठी मांग को भी पूरी ईमानदारी के साथ सिरे चढ़वाने का भरसक प्रयास करूंगा। हक निश्चित तौर पर मिलेगा, कार्तिकेय शर्मा समारोह में बतौर मुख्यातिथि बोलते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मेरे पिता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने आर्थिक आधार पर आरक्षण और दोहलीदार जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए अहम रोल अदा किया था।

मेजर जनरल आशीष खुराना ने बैटल एक्स डिवीजन की कमान संभाली

जैसलमेर (हिंस)। मेजर जनरल आशीष खुराना ने प्रतिष्ठित बैटल एक्स डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने मेजर जनरल हरतेज सिंह बजाज का स्थान लिया। औपचारिक हस्तांतरण समारोह शनिवार को हुआ। दोनों अधिकारियों ने जैसलमेर वॉर मेमोरियल पर भारतीय सेना के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र, मेजर जनरल खुराना को 11 दिसंबर 1993 को सेना वायु रक्षा में कमीशन मिला था। वह रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, उच्च कमान पाठ्यक्रम, महू और प्रतिष्ठित रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज, यूनाइटेड किंगडम से स्नातक हैं। तीन दशकों से अधिक के विशिष्ट सैन्य करियर के साथ, मेजर जनरल खुराना ने व्यापक संचालन अनुभव प्राप्त किया है।

तपस्वी सीएम योगी ने लहराया सनातन का परचम : अखाड़ा परिषद

प्रयागराज (हिंस)। तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व में सनातन का ऐसा परचम लहराया है, जो आज तक किसी ने नहीं किया है। 2019 का कुंभ दिव्य और भव्य था और सीएम योगी की अगुवाई में महाकुंभ 2025 उससे भी ज्यादा दिव्य और भव्य होगा। ये बातें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने कहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का मान बढ़ाने वाला बताया। उल्लेखनीय है कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार के महाकुंभ को अलौकिक रूप देने में लगे हैं, जिसमें देश दुनिया के साधु संत भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में देश भर के शीर्ष महात्माओं का प्रयागराज में आगमन शुरू हो चुका है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी भी प्रयागराज पहुंचकर अखाड़ों की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस बार टूटेंगे सभी रिकॉर्ड। उन्होंने कहा कि तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन का ऐसा परचम

लहराया है कि देश विदेश की नजरें भारत पर आकर टिक गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन की परम्परा को बुलंद किया है। देश के ऐसे शीर्ष नेतृत्व ही दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक महा आयोजन को साकार कर सकते हैं। दिव्यता और भव्यता के लिहाज से इस बार का महाकुंभ सबसे अलौकिक होने जा रहा है, जिसमें पुराने सभी रिकार्ड ध्वस्त होने जा रहे हैं। नया गुरु नहीं, बनाते हैं गुरु भाई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने निरंजनी अखाड़ा के माहात्म्य के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि निरंजनी अखाड़ा के संत देव सेनापति कार्तिकेय का अनुसरण करते हैं। इसके अलावा यहां दीक्षा लेने के बाद सभी को गुरु भाई बनाया जाता है। यहां किसी को अलग से नया गुरु बनाने की कोई परम्परा नहीं है। हम सबके गुरु निरंजन देव हैं। तीन साल की मेहनत का श्रद्धालुओं को मिलेगा प्रसाद महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से वर्षों पूर्व तैयारी शुरू हो जाती है। इस बार के महाकुंभ को लेकर 3 साल पहले से ही योजनाएं शुरू कर दी गईं। यहां भक्तों के प्रसाद के लिए करीब 3 साल पहले से ही जरूरी संसाधन जुटाए जाने लगे। जिसमें देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और स्वादिष्ट प्रसाद का इंतजाम किया गया है। जिसमें पांच-पांच हजार लोग एक पंक्ति में बैठकर महाकुंभ के पवित्र प्रसाद का आनंद लेंगे। 1008 कुंडीय यज्ञ, जड़ी बूटियों की सुगंध से महक उठेगा समूचा महाकुंभ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने बताया कि इस बार के महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए साधु संत भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र सुगंधित जड़ी बूटियों के हवन से महक उठेगा। यहां सभी सनातनी एकत्र होने जा रहे हैं। महाकुंभ में दुनिया भर के संत महात्माओं का आगमन हो रहा है। जिसके लिए यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण वायुमंडल को सुगंधित बनाए जाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे सनातन बोर्ड के गठन पर फैसलाअखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 26 जनवरी को महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश भर के प्रमुख साधु संत हिस्सा लेंगे।

मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन में 300 लोगों की समस्याएं सुनीं

गोरखपुर (हिंस)। जनपद में प्रवास पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सभी की समस्याएं सुनी और कहा कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान करने को तत्पर और प्रतिबद्ध है। किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हर पीड़ित की समस्या का निराकरण किया जाएगा, सबको न्याय मिलेगा। इसे लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी की समस्या का शीघ्रता से गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।जनता दर्शन में गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे। और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने करीब 300 लोगों से मुलाकात की। लोगों के प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए तत्पर और प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाएं। उनकी समस्याओं का समाधान कर उसे संतुष्ट करें। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमीन के विवाद की शिकायतों पर योगी ने कहा कि यदि विवाद पारिवारिक हो तो संबंधित पक्षों के बीच वार्ता कराई जाए और बात न बनने पर विधिक कार्यवाही की जाए। यदि कोई दबंग किसी की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कराकर शासन में उपलब्ध कराया जाए। राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता वह निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।गोरखनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों के साथ मंदिर आए बच्चों को प्यार, दुलार और आशीर्वाद दिया। बच्चों को अपने पास बुलाकर उनसे बातचीत की। नाम पूछने के साथ हंसी ठिठोली की। उनसे पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और खूब पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बच्चों को योगी ने चॉकलेट गिफ्ट कर विदा किया।

टॉप टेन अपराधियों में शुमार कुख्यात सूरज झा दो सहयोगियों के साथ गिरफ्तार

अररिया (हिंस)। अररिया जिला पुलिस ने टॉप टेन अपराधियों में शुमार कुख्यात अपराधी सूरज झा को उसके दो अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से दो देशी कट्टा, एक पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस, दो मैगजीन बरामद किया है।जानकारी एसपी अमित रंजन ने दी। एसपी अमित रंजन ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जिला के टॉप टेन अपराधियों में शुमार कुख्यात भरगामा थाना क्षेत्र के आदिरामपुर वार्ड संख्या एक का रहने वाला सूरज झा पिता -शैलेन्द्र झा अपने सहयोगियों के साथ आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर एसपी के द्वारा फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा और भरगामा थाना पुलिस एवं डीआईयू टीम के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया।सूचना के आलोक में विशेष टीम के द्वारा छापेमारी की गई तो सूरज

झा के साथ आदिरामपुर वार्ड संख्या छह के रहने वाले सूरज कुमार शर्मा पिता -हीरालाल शर्मा, भरगामा थाना क्षेत्र के मनुल्लाहपट्टी वार्ड संख्या छह के छोटू कुमार मंडल पिता -श्याम सुंदर मंडल को दो देशी कट्टा, एक पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस, दो मैगजीन के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया।एसपी ने बताया कि गिरफ्तार कुख्यात सूरज झा के खिलाफ भरगामा और रानीगंज थाना में आधा दर्जन से अधिक लूट, गबन, मद्य निषेध, मारपीट और हत्या का मामला दर्ज है। छापेमारी दल में भरगामा थानाध्यक्ष राकेश कुमार, अपर थानाध्यक्ष दीपक कुमार, सब इंस्पेक्टर राजनारायण यादव, रूपा कुमारी, डीआईयू शाखा के एसआई विवेक प्रसाद, नागेन्द्र कुमार, भरगामा थाना के एएसआई प्रमोद कुमार सिंह, विभाष कुमार के साथ डीआईयू की टीम और सशस्त्र बल के जवान मौजूद थे।

नीतीश ने बिहार में किया विकास के साथ समता मूलक समाज की स्थापना : रामनाथ ठाकुर

नवादा (हिंस)। नवादा के गांधी मैदान में रविवार को जनता दल यूनाइटेड का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य के एक दर्जन नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास का पुरोधा बताते हुए उनकी उपलब्धियां को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी ने की तथा संचालन महासचिव जयशंकर चंद्रवंशी ने की। सम्मेलन में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलकर विकास तथा जंगल राज की खात्मे में के साथ के समता मूलक समाज की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही लोहिया के व्यावहारिक समाजवाद की स्थापना की। इस कारण आज उन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की उपलब्धियां को जन-जन तक कार्यकर्ता पहुंचाएं, तभी एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार का गठन किया जाएगा। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव भारतीय प्रशासन सेवा के पूर्व अधिकारी मनीष वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही विकसित बिहार का सपना पूरा करेंगे। 19 वर्षों में उन्होंने बिहार में जंगल राज के खाते में के साथही विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार किया है। इसलिए निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष हैं। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि नीतीश कुमार के विकास का एजेंडा का पूरे देश कायल है। उन्होंने कहा कि बिहार की बदहाली को दूर करने में नीतीश कुमार ने अपना जीवन लगा दिया है।बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाएं तभी विकसित बिहार की परिकल्पना साकार हो सकती है। विधान पार्षद

नीरज कुमार ने 19 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास की उपलब्धियां को गिनाते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो आज बिहार रसातल में चला जाता। राजद से जदयू के समर्थन में आये नवादा के विधान पार्षद अशोक यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार का चौहमुखी विकास किया है। जिससे प्रभावित होकर मैं उनके दल में आया हूं। ताकि मैं बिहार के विकास में अपना योगदान कर सकूं। जदयू में आने के लिए सभी नेताओं ने उनका स्वागत करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार में पुरोधा के रूप में काम कर आज देश के मानचित्र पर बिहारी को गौरव दिलाया। जिला अध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा है कि जिले का कार्यकर्ता नीतीश के आदर्शों को अपनाकर उनकी उपलब्धियां को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में नवादा जिले की पांच विधानसभा क्षेत्र की सीटों को एनडीए के झोली में डाल दिया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता मनोहर पासवान, हरि कृपाल, प्रमिला प्रजापति, जयशंकर चंद्रवंशी, नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन व पार्टी के कोषाध्यक्ष संजय साहू, नगर परिषद के अध्यक्ष पिंकी कुमारी आदि ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए नीतीश सरकार के उपलब्धियां को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। गांधी मैदान में जुटे हजारों कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाकर नीतीश कुमार के बेहतर कार्यों की सराहना करते हुए नवादा जिले की सभी सीटों को नीतीश की झोली में डालने का अपना संकल्प दोहराया है।

वैश्विक रुझानों, ब्याज दर पर आरबीआई के फैसले तय करेंगे शेयर बाजारों की चाल

कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिकी डॉलर के रुख से भी बाजार प्रभावित होगा

मुंबई

इस सप्ताह वैश्विक रुझानों, व्यापक आर्थिक आंकड़ों और ब्याज दर पर आरबीआई के फैसले शेयर बाजारों की दिशा तय कर सकते हैं। बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि इस सप्ताह निवेशक ऑटो बिक्री के मासिक आंकड़ों पर भी निगाहें रहेंगी। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि बाजार सोमवार को 5.4 प्रतिशत की निराशाजनक जीडीपी वृद्धि पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आगामी आरबीआई नीति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें ब्याज दर निर्णय और टिप्पणी, दोनों पर ही निवेशकों की नजर होगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक मोर्चे पर, भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से रूस-यूक्रेन की स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई है। भारत, अमेरिका और चीन से विनिर्माण पीएमआई जैसे महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक आंकड़े भी बाजार को प्रभावित करेंगे। विश्लेषकों ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिकी डॉलर के रुख से भी बाजार प्रभावित होगा। विनिर्माण और खनन क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन के साथ ही कमजोर खपत के कारण चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर दो साल के निचले स्तर 5.4 प्रतिशत पर पहुंच गई। देश हालांकि अभी भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाजारों ने काफी उतार-चढ़ाव देखा, हालांकि सप्ताह के अंत में बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि बाजार का नजरिया भारत के विनिर्माण पीएमआई, सेवा पीएमआई, ब्याज दर पर फैसले, अमेरिकी एसएंडपी वैश्विक समग्र पीएमआई, विनिर्माण पीएमआई, सेवा पीएमआई, गैर-कृषि रोगजार के आंकड़ों जैसे प्रमुख घरेलू और वैश्विक आर्थिक कारकों से प्रभावित होगा।

न्यूज ब्रीफ

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर की बिक्री 20 प्रतिशत बढ़कर 6,019 इकाई पर, विंडसर ने 3,144 इकाइयों की बिक्री के साथ दूसरे महीने भी तोड़तोड़ की

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख मोटरकार कंपनी जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने रविवार का एक मुख्य घोषणा की कि नवंबर 2024 तक उनकी थोक बिक्री 20 प्रतिशत बढ़कर 6,019 इकाई पहुंच गई है। कंपनी ने यह भी कहा कि उनके इलेक्ट्रिक वाहन विंडसर ने 3,144 इकाइयों की बिक्री के साथ दूसरे महीने भी तोड़तोड़ की है। कंपनी ने बताया कि उनकी कुल मासिक बिक्री में नए ऊर्जा वाहनों (एनईवी) का हिस्सा 70 प्रतिशत है। यह उछाल उनके इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है और उन्हें बाजार में भी मजबूती का अहसास करवाता है। इस ताजा विकेन्द्रीकरण के साथ जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा को लेकर नए उत्साह का संकेत दिया है। उनकी विंडसर श्रृंखला और एनईवी सेगमेंट में उच्च बिक्री उनके उद्यमी रुझान के प्रति विश्वास को मजबूत कर रही है।

एमएंडएम मौजूदा बिक्री नेटवर्क के जरिए ईवी बेचेगी, एक जगह उपलब्ध होंगे सभी विकल्प

नई दिल्ली। महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) ने घोषणा की है कि वे अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपने मौजूदा बिक्री नेटवर्क के माध्यम से बेचेंगे। यह नई पहल का मकसद है कि ग्राहकों को एक ही स्थान पर सभी विकल्प उपलब्ध कराएं जाएं। इस उद्देश्य को पूरा करते हुए कंपनी ने दो नए इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल - बीई 6ई और एक्सईवी 9ई का विस्तार किया है। एमएंडएम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसमें व्यापक रूप से भाग लेने की योजना बताते हुए कहा कि हम बिक्री चैनल को एक समान रखना चाहते हैं ताकि ग्राहक को आईसीई और ईवी के बीच चयन करने की सुविधा मिले। वे एक संवेदनशील प्रश्न के जवाब में यह भी बताते हैं कि क्या कंपनी अपने ईवी रेंज के लिए एक अलग बिक्री नेटवर्क की स्थापना करेगी। जारी किए गए बयान में यह भी कहा कि एमएंडएम एक विशेष टीम की स्थापना कर रही है जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और सेवा को संभालेगी। उन्होंने बताया कि नए वाहन मॉडल संबंधी डिलीवरी को फरवरी-मार्च के बीच में शुरू किया जाएगा और वे आशा कर रहे हैं कि ग्राहकों को यह नए विकल्प पसंद आएंगे। इस पहल के बाद एमएंडएम ने ईवी बिक्री और सेवा को सुधारने के लिए एक विशेष धारा स्थापित करने की योजना बनाई है जिससे ग्राहकों को अधिक सुविधा मिले।

रेवफिन का पांच वर्षों में 20 लाख वाहन वित्तपोषित करने का लक्ष्यः सीईओ

नई दिल्ली। डिजिटल वाहन फाइनेंस कंपनी रेवफिन ने घोषित किया है कि उनका मुख्य लक्ष्य है अगले पांच वर्षों में 20 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को वित्तपोषित करना। कंपनी के संस्थापक और सीईओ समीर अग्रवाल ने इस उद्देश्य को पाने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने का निर्णय किया है। रेवफिन ने मार्च 2026 तक अपने लक्ष्य के हिसाब से लगभग 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज देने का भी निर्णय किया है। कंपनी का प्रमुख ध्यान इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के वित्तपोषण पर है। अग्रवाल ने बताया कि कंपनी इक्विटी के जरिये अगले 18 महीनों में पांच करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने की योजना बना रही है। अब तक रेवफिन ने लगभग 75,000 वाहनों को वित्तपोषित किया है और इसका अनुमान है कि इस साल के अंत तक लगभग 25,000 वाहनों को और वित्तपोषित किया जाएगा। अग्रवाल ने बताया कि रेवफिन ने कुल 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज दिए हैं, और उनमें से लगभग 400 करोड़ रुपये केवल इस वर्ष जारी किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी ने अगले 18 महीनों में ऋण वितरण को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा है।

लगातार 5वें महीने बढ़ी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत, घरेलू गैस के दाम में बदलाव नहीं

5 महीने में 172 रुपये से ज्यादा महंगा हो गया कॉमर्शियल गैस सिलेंडर

नई दिल्ली

एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी हो गई है। सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत से ही लागू भी हो गई है। ये बढ़ोतरी 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में हुई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में लगातार पांचवें महीने बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमत के अनुसार अब कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1,802 रुपये से बढ़ कर 1,818.50 रुपये हो गई है।

दिल्ली की तरह देश के अन्य हिस्सों में भी कॉमर्शियल सिलेंडर से बढ़ी हुई कीमत पर मिल रहा है। दिल्ली के अलावा अन्य मेट्रो शहरों में से कोलकाता में 19 किलोग्राम वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 1,911.50 रुपये से बढ़ कर 1,927 रुपये का हो गया है। इसी तरह मुंबई में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1,754.50 रुपये से बढ़ कर 1,771 रुपये हो गई है। चेन्नई में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1,964.50 रुपये से बढ़ कर 1,980.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है।

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में जहां पांचवीं बार बढ़ोतरी हुई है, वहीं 14.2 किलोग्राम वजन वाले घरेलू गैस सिलेंडर यानी रसोई गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में आखिरी बार पिछले साल अगस्त में बदलाव किया गया था। उस समय रसोई गैस की कीमत 100 रुपये प्रति सिलेंडर कम हुई थी। उसके बाद करीब डेढ़ साल की अवधि में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीमत में बदलाव नहीं होने के कारण घरेलू एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 803 रुपये में मिल रहा है, जबकि चेन्नई में इसकी कीमत 818.50 रुपये के स्तर पर बनी हुई है। इसी तरह मुंबई में 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर 802.50 रुपये में और कोलकाता में घरेलू गैस सिलेंडर 829 रुपये में मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर का इस्तेमाल घरों में खाना बनाने के काम में किया जाता है, जबकि रेस्टोरेंट, पोल्ट्री, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन जैसे नॉन डोमेस्टिक जगह पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत आखरी बार 5 महीने पहले जुलाई के महीने में घटाई गई थी। 1 जुलाई 2024 को कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1,646 रुपये थी। हालांकि अगस्त के महीने से लगातार कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से पिछले 5 महीने के दौरान दिल्ली में इसकी कीमत 172.50 रुपये बढ़ चुकी है।

देश की नौ प्रमुख कंपनियों का मार्केट कैप 2.29 लाख करोड़ बढ़ा

नई दिल्ली

रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान घरेलू कंपनी बनी रही

पिछले सप्ताह देश की प्रमुख 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में नौ का कुल बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में 2,29,589.86 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी देखी गई। इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम को सबसे अधिक लाभ हुआ। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का मूल्यांकन 60,656.72 करोड़ रुपये बढ़कर 6,23,202.02 करोड़ रुपये, एचडीएफसी बैंक का मूल्यांकर 39,513.97 करोड़ रुपये बढ़कर 13,73,932.11 करोड़ रुपये, रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 35,860.79 करोड़ रुपये बढ़कर 17,48,991.54 करोड़ रुपये, भारती एयरटेल का बाजार मूल्यांकन 32,657.06 करोड़ रुपये बढ़कर 9,26,725.90 करोड़ रुपये, भारतीय स्टेट बैंक का बाजार मूल्यांकन 20,482 करोड़ रुपये बढ़कर 7,48,775.62 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक का मूल्यांकन 15,858.02 करोड़ रुपये बढ़कर 9,17,724.24 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और आईटीसी का मूल्यांकन भी बढ़ा।

हालांकि, इंफोसिस का बाजार मूल्यांकन 18,477.5 करोड़ रुपये घटकर 7,71,674.33 करोड़ रुपये रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान घरेलू कंपनी बनी रही, जिसके बाद टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थान रहा।

रूस ने कोंडोर-एफकेए रडार सैटेलाइट किया लांच, सोयुज-2.1ए रॉकेट ने सफलतापूर्वक उपग्रह को लक्षित कक्षा में पहुंचाया

व्लादिवोस्तोक

रूस ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सोयुज-2.1ए रॉकेट के माध्यम से कोंडोर-एफकेए नंबर 2 रडार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह उपग्रह देश के लिए ऑल-वेदर, राउंड-द-क्लॉक अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए महत्वपूर्ण है। सोयुज-2.1ए रॉकेट ने सफलतापूर्वक उपग्रह को लक्षित कक्षा में पहुंचाया। इस रॉकेट का प्रक्षेपण सुविधाएं भूमि पर से होती हैं, जो इसे अन्य तकनीकों से अलग बनाती है। कोंडोर-एफकेए श्रृंखला के उपग्रह अपनी नेतृत्वक क्षमताओं के साथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन उपग्रहों की विशेषता यह है कि वे बादलों के पार से भी धरती पर नजर रख सकते हैं और अंधेरे में काम कर सकते हैं।

इसके अलावा इनकी विशेषता इन्हें मैपिंग, पर्यावरण निगरानी, प्राकृतिक संसाधन अन्वेषण, और मार्गदर्शक जहाजों को सहायता पहुंचाने में मादक बनाती है। पहले दो उपग्रहों को 2013 और 2014 में लॉन्च किया गया था, जबकि कोंडोर-एफकेए नंबर 1 ने 2023 में कक्षा में प्रवेश किया था। वर्तमान में दो और उपग्रह निर्माणाधीन हैं, जिसमें तीसरा कोंडोर-एफकेए 2026 में लॉन्च किया जाएगा। प्रत्येक कोंडोर-एफकेए उपग्रह का वजन लगभग 1,050 किलोग्राम होता है और इसकी लाइफ पांच साल की होती है।

हमारे समूह पर हुए हमलों ने हमें मजबूत बनाया हैः गौतम अदाणी

अदाणी ने कहा, सपने जितने बोल्ड होंगे, उतना ही सामना कठिन होगा

जयपुर

राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी अवॉर्ड्स जगमगाईं, जहां अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने अपनी विचारधारा को साझा किया।

उन्होंने कहा कि हर हमला उन्हें और मजबूत बनाता है और हर बाधा एक सीढ़ी बना देता है। इस समारोह में गौतम अदाणी ने पहली बार अमेरिकी न्याय विभाग के चर्चे किए। उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि उनकी विचारधारा कैसे उन्हें समृद्धि की ओर ले जा रही है।

गौतम अदाणी ने समूह के खिलाफ शॉर्ट-सेलिंग का भी उदाहरण दिया, जो दिखाता है कि उनकी संघर्षमय यात्रा में किसी भी चुनौती का कैसे सामना किया गया है। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने सिद्धांतों की प्रतिबद्धता बनाए रखने का प्रमाण दिया।

उन्होंने ध्यान दिया कि सपने जितने बोल्ड होंगे, उतना ही सामना कठिन होगा परंतु उन्हें आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौतम अदाणी की ये विचारधारा और संघर्ष के दुनिया में एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो हमें यह सिखाते हैं कि उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि इन वर्षों में मैं यह स्वीकार करता आया हूं कि जिन बाधाओं का हम सामना करते हैं, वे (दूसरों से) आगे होने की कीमत हैं। आपके सपने जितने बोल्ड होंगे, दुनिया आपको उतना ही अधिक परखेगी। लेकिन आपको आगे बढ़ने, यथास्थिति को चुनौती देने और एक ऐसा रास्ता बनाने का साहस मिलना चाहिए जिस पर पहले कभी कोई न चला हो।

पायनियरिंग करने का अर्थ है अज्ञात को अपनाना, सीमाओं को तोड़ना और अपने दृष्टिकोण पर तब भी विश्वास करना जब दुनिया इसे अभी तक नहीं समझ पाई हो।

दिसंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सोना, चांदी में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली

दिसंबर के पहले दिन ही घरेलू सर्राफा बाजार में सोने के भाव में मामूली गिरावट आई है। हालांकि चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। के कारोबार में सोना 100 रुपये से 110 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है। भाव में आई इस गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 78,150 रुपये से लेकर 78,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है।

इसी तरह 22 कैरेट सोना 71,650 रुपये से लेकर 71,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बना हुआ है। चांदी के भाव बदलाव नहीं होने के कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में इसकी कीमत भी 91,500 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है।

देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 78,150 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 71,650 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 78,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 71,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 78,050 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 71,550 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 78,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 71,500 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 78,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 71,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 78,150 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 71,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। वहीं, पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 78,050 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि 22 कैरेट सोना 71,550 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह जयपुर में 24 कैरेट सोना 78,150 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 71,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोना सस्ता हुआ है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 78,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 71,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

आईसीसी चेयरमैन के रूप में जय शाह ने की अपने कार्यकाल की शुरुआत

दुबई

भारतीय क्रिकेट को नई ऊचाइंयों पर पहुंचाने में अहम योगदान देने के बाद जय शाह ने रविवार यानी 1 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के चेयरमैन के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत कर दी है। वह ग्रेग बार्कले का स्थान लेंगे। बार्कले नवंबर 2020 से इस पद पर थे। जय शाह इस साल अगस्त में आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए थे। आईसीसी ने रविवार को इस बात की जानकारी दी।

आईसीसी चेयरमैन के रूप में जय शाह ने अपने पहले वक्तव्य में अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, जिसमें लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने और महिला खेल के विकास में और तेजी लाना शामिल है। शाह ने एक बयान में कहा कि मैं आईसीसी चेयरमैन की भूमिका के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं और आईसीसी निदेशकों और सदस्य बोर्डों के समर्थन और विश्वास के लिए आभारी हूं। उन्होंने कहा कि यह खेल के लिए एक रोमांचक समय है क्योंकि हम लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहे हैं और दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए क्रिकेट को अधिक समावेशी और आकर्षक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम कई प्रारूपों के सह-अस्तित्व और महिलाओं के खेल के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाएं हैं और मैं इन अवसरों का लाभ उठाने तथा खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आईसीसी टीम और सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।

शाह ने पिछले चार वर्षों में आईसीसी की उपलब्धियों में बार्कले के योगदान की सहारना की। उन्होंने कहा कि मैं पिछले चार वर्षों में इस पद पर उनके नेतृत्व के लिए तथा इस अवधि के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों के लिए ग्रेग बार्कले को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं वैश्विक मंच पर खेल की पहुंच और विकास का विस्तार करने के लिए आईसीसी टीम और सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।

न्यूज ब्रीफ

कूच बेहार अंडर-19 टूर्नामेंट : बिहार के सुमन ने लिए एक पारी में सभी 10 विकेट

मुम्बई । यहां जारी कूच बेहार अंडर-19 टूर्नामेंट में बिहार के एक युवा गेंदबाज सुमन कुमार ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। सुमन ने एक पारी में सभी 10 विकेट लिए हैं। सुमन ने राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में सभी विकेट लिए। इस दौरान सुमन ने हैट्रिक भी लगायी। उन्होंने 36वें ओवर में मोहित भागतानी, अनस और सचिन शर्मा को लगातार तीन गेंदों पर आउट कर हैट्रिक पूरी की। इसी के साथ ही इस गेंदबाज ने इस सत्र में अपने 22 विकेट पूरे किये हैं। भारत के घरेलू टूर्नामेंट में ये दूसरी बार है जब किसी गेंदबाज ने एक पारी में सभी 10 विकेट लिए हैं। सुमन से पहले हरियाणा के अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में केरल के खिलाफ ये काम किया था। बिहार ने इस मैच में पहली पारी में 467 रन बनाये। इसमें दिपेश गुप्ता के नाबाद 183, पृथ्वी राज के 128 रनों का अहम योगदान रहा। इसके जबाव में राजस्थान की टीम 182 रनों पर सही सिमट गयी । सुमन ने अकेले ही पूरी राजस्थान टीम को तीसरे दिन आउट कर दिया। । राजस्थान को फॉलोऑन मिला और उसने तीसरे दिन का अंत दो विकेट के नुकसान पर 173 रनों के साथ किया।

डब्लयूटीसी फाइनल की दो सीटों के लिए 4 टीमों में होगा मुकाबला

मुम्बई । आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्लयूटीसी) फाइनल की दौड़ में अब केवल चार टीमें ही बची हैं। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही टेस्ट में मिली जीत से जहां उसकी दावेदारी मजबूत हुई है। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही टेस्ट में हार से न्यूजीलैंड का सफर समाप्त हो गया है। फाइनल की दो सीट के लिए इस वक्त चार टीमों में मुकाबला है। इसमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की टीम शामिल है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में बने रहने के लिए न्यूजीलैंड की टीम को तीन में तीनों ही मुकाबले में जीत दर्ज करनी थी पर ऐसा हुआ नहीं। भारतीय टीम इस समय विश्व टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में शीर्ष पर कायम है। श्रीलंका को हराकर दक्षिण अफ्रीका दूसरे जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे स्थान पर खिसक गई है। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त चौथे स्थान पर है हालांकि अब वह रेस से बाहर हो गयी है। श्रीलंका की टीम को अपनी संभावनाएं बनाने बचे हुए तीन मैच जीतने होंगे।

न्यूजीलैंड की टीम पहले टेस्ट में हार के साथ ही डब्लयूटीसी की रेस से बाहर हुई, भारतीय टीम की संभावनाएं बढ़ीं

मुम्बई । न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में मिली हार के साथ ही आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्लयूटीसी) की रेस से बाहर हो गयी है। न्यूजीलैंड टीम के बाहर होने के साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम की संभावनाएं बढ़ गयी हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। पांच मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर भारत ने फाइनल की अपनी दावेदारी और बेहतर की है। वहीं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही सीरीज पर सबकी नजर थी जहां न्यूजीलैंड की करारी हार से भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों को लाभ हुआ है। टूर्नामेंट में अभी भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका रेस में शामिल है। न्यूजीलैंड की टीम को इंग्लैंड से मिली पहले टेस्ट मैच की हार ने फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया है। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच इंग्लिश टीम ने 8 विकेट से जीतकर न्यूजीलैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फाइनल में जगह बनाने के लिए न्यूजीलैंड की टीम को इंग्लैंड के खिलाफ तीनों ही टेस्ट मैच में जीत हासिल करना था। पहला मुकाबला हारने के बाद अब वह आखिरी दो मैच जीतकर भी उसके लिए फाइनल में जगह बनान संभव नहीं है। इस समय भारतीय टीम अंक तालिका में शीर्ष पर कायम है। उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बचे हुए 4 मैच में से कम से कम तीन में जीत चाहिए।

यूएसपीएल सीजन 3 : न्यू जर्सी टाइटंस को हरा न्यूयॉर्क काउबॉयज फाइनल में

फ्लोरिडा

फ्लोरिडा के ब्रोवार्ड काउंटी स्टेडियम में आयोजित यूनाइटेड स्टेट्स प्रीमियर लीग (यूएसपीएल) के एलिमिनेटर मुकाबले में कप्तान जेक लिंटॉट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को फाइनल में जगह दिलाई। करो या मरो के इस गेम में न्यूयॉर्क काउबॉयज ने न्यू जर्सी टाइटंस को 30 रनों से शिकस्त दी। इस जीत के साथ काउबॉयज ने फाइनल में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, जहां उनका सामना टॉप पर मौजूद मैरीलैंड मेवरिक्स के साथ होगा।

तीन हार के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करने वाले न्यूयॉर्क काउबॉयज ने असाधारण खेल दिखाते हुए लगातार 4 मुकाबले जीतकर ट्रॉफी की मजबूत दावेदारी पेश की है।

न्यूयॉर्क काउबॉयज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ शुरुआत की और मुख्तार अहमद की 41 गेंदों में 59 रन की शानदार पारी की बदौलत पावरप्ले में 63 रन बोर्ड पर लगा दिए। जिसके बाद पारी कुछ लड़खड़ाई, लेकिन अंत में परवीन कुमार के 13 गेंदों में महत्वपूर्ण 19 और कप्तान लिंटॉट के 10 रनों ने टीम को 9 विकेट के नुकसान पर 152 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया।

लक्ष्य का पीछा करने के दौरान, जब न्यू जर्सी टाइटंस को 18 गेंदों पर 36 रनों की आवश्यकता थी। तब कप्तान लिंटॉट ने 18वें ओवर की जिम्मेदारी खुद उठाई और जैसा वह चाहते थे वैसा ही हुआ। जहां इस ओवर के पहले तक टाइटंस का स्कोर 117/5 था, वहीं इस ओवर के बाद टीम 119/9 के स्कोर पर पहुंच गई और 19वां ओवर खत्म होते-होते 122 रनों पर धराशाई हो गई। काउबॉयज के लिए जेक लिंटॉट और परवीन कुमार दोनों ने ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 3-3 विकेट झटके।

यूपी रुद्रास ने हार्दिक सिंह को अपना कप्तान घोषित किया

लखनऊ। स्टार मिडफील्डर हार्दिक सिंह को हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) के आगामी सत्र के लिए यूपी रुद्रास ने अपना कप्तान घोषित किया है। यदु स्पोर्ट्स के स्वामित्व वाली यूपी रुद्रास ने एक मजबूत टीम तैयार की है, जिसमें युवा सनसनी प्रियोबर्ता तलेम, गुरजोत सिंह के साथ-साथ भारतीय और अंतरराष्ट्रीय हॉकी के कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें ललित कुमार उपाध्याय, सिमरनजीत सिंह, लार्स बाल्क और केन रसेल हैं। यदु स्पोर्ट्स के सह-संस्थापक माधवकृष्ण सिंघानिया ने एक बयान में यदु स्पोर्ट्स परिवार की ओर से हार्दिक को टीम का कप्तान घोषित किए जाने पर बधाई देते हुए कहा कि मौजूदा टीम में शानदार हॉकी खेलने और लोगों का दिल जीतने के लिए सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं। हॉकी इंडिया लीग का बड़ा, बेहतर और साहसिक संस्करण वैश्विक हॉकी पावरहाउस के रूप में भारत के कद को और बढ़ाएगा और मेरा मानना है कि इस कद की प्रतियोगिता में भविष्य के लीडर्स को तैयार करने की क्षमता है। टीम के मुख्य कोच पॉल वैन ऐस ने कहा कि नीलामी में हार्दिक हमारी पहली पसंद थे और हमें पूरा भरोसा था कि वे टीम की अगुआई करेंगे। उन्हें लगातार भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करते देखना और लगातार दो ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा होना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हमें यकीन है कि खेल की बारीकियों और पेचीदगियों को समझने की उनकी क्षमता के साथ, वे न केवल टीम का नेतृत्व करेंगे बल्कि अपने आस-पास के लोगों से भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाएंगे।

शमी की फिटनेस और प्रदर्शन की समीक्षा कर रहा बीसीसीआई

मुम्बई

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अभी बंगाल की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं। शमी को राष्ट्रीय टीम में जगह देने से पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) उनकी फिटनेस को लेकर आश्वस्त होना चाहता है। चोट के बाद वापसी कर रहे शमी की फिटनेस और प्रदर्शन की समीक्षा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पदर्शन के आधार पर होगी। राष्ट्रीय चयनकर्ता और बीसीसीआई की स्पोर्ट्स साइंस टीम उनकी फिटनेस का गहरानी से निरीक्षण कर रही है।

स्पोर्ट्स साइंस विभाग के प्रमुख नितिन पटेल और चयनकर्ता एसएस दास राजकोट में शमी के प्रदर्शन पर नजर रख रहे हैं। शमी को टीम में शामिल करने से पहले बीसीसीआई पक्का करना चाहता है कि वह टेस्ट क्रिकेट की मांगों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हों। इस दौरान शमी के दैनिक वर्कलोड, प्री-मैच और पोस्ट-मैच स्थिति पर नजर रखी जा रही है। शमी ने अब तक चार मैच खेले हैं, जिनमें उनका प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। उन्होंने पंजाब के खिलाफ 1/46, हैदराबाद के खिलाफ 3/21, मिजोरम के खिलाफ 0/46 और मध्य प्रदेश के खिलाफ 0/38 का प्रदर्शन किया। फिटनेस के लिहाज से वह इन मुकाबलों में बेहतर नजर आए हैं। इससे पहले उन्होंने रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए 7 विकेट हासिल किए थे।

बीसीसीआई और टीम प्रबंधन शमी की प्रगति पर नियमित अपडेट ले रहा है। चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर और उप-कप्तान जसप्रीत बुमराह ने शमी को टीम का अहम हिस्सा बताया है। बुमराह ने कहा, शमी हमारी टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। प्रबंधन उनकी स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है, और उम्मीद है कि वह जल्द टीम के साथ जुड़ सकते हैं। शमी के आगे के प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई उनका आंकलन करेगा।

एडिलेड टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन का प्रयास करुंगा : बोलैंड

कैनबरा

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने कहा है कि वह 6 दिसंबर से एडिलेड में खेले जाने वाले बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में खेलने के लिए तैयार हैं। बोलैंड को तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के चोटिल होने के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर होने के बाद शामिल किया गया है। बोलैंड का मानना है कि वह लय में हैं और अब भारत के खिलाफ एडिलेड में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में बेहतर प्रदर्शन का प्रयास करेंगे।

बोलैंड ने कहा, मैंने इस सीजन की शुरुआत में बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है पर मुझे लगता है कि मैंने इतना क्रिकेट खेल लिया है कि मैं वाकई अच्छी स्थिति में हूं। मेरा शरीर अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। मुझे कुछ छोटी-मोटी चोटें लगी थीं, लेकिन अब मैं फिट हूं। एडिलेड में गुलाई गेंद से खेला जाने वाला मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए पांच मैचों की सीरीज बराबर करने का अच्छा अवसर है। मेजबान टीम पर्थ में हुए पहले टेस्ट में भारत से करारी हार से उबरने का प्रयास करेगी। बोलैंड मानना है कि उनकी टीम वापसी के लिए अपनी ओर से पूरे प्रयास करेगी।

हॉकी इंडिया ने जूनियर एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा की

नई दिल्ली

हॉकी इंडिया ने रविवार को आगामी महिला जूनियर एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा की। यह प्रतियोगिता 7 से 15 दिसंबर तक ओमान के मस्कट में खेली जाएगी। पिछले साल फाइनल में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर अपना पहला खिताब हासिल करने के बाद गत चैंपियन के रूप में भारत बड़ी उम्मीदों के साथ इस टूर्नामेंट में उतरेगा।

प्रतियोगिता में 10 टीमें भाग लेंगी जिन्हें दो पूलों में विभाजित किया गया है। भारत को पूल ए में चीन, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश के साथ रखा गया है, जबकि पूल बी में दक्षिण कोरिया, जापान, चीनी ताइपे, हांगकांग चीन और श्रीलंका शामिल हैं।

भारतीय जूनियर महिला टीम की कमान ज्योति सिंह के हाथों में होगी, जबकि साक्षी राणा उप-कप्तान होंगी। निधि और अदिति माहेश्वरी के रूप में टीम में दो गोलकीपर हैं, जबकि डिफेंस की कमान मनीषा, ज्योति सिंह, लालथंतलुआंगी, पूजा साहू और ममता ओरम संभालेंगी। मिडफील्डर में वैष्णवी विट्ठल फाल्के, सुनीता टोप्पो, इशिका, रजनी केरकेट्टा, साक्षी राणा और खैदेम शिलेमा चानू जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। अग्रिम पंक्ति में दीपिका, ब्यूटी डुंगडुंग, कनिका सिवाच, मुमताज खान और लालरिनपुई अटैक का नेतृत्व करेंगी। बिनिमा धन और हिमांशी शरद गवांडे को वैकल्पिक खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है।

टीम के चयन पर कोच तुषार खांडेकर ने जारी बयान में कहा कि हम महिला जूनियर एशिया कप में अपने खिताब की रक्षा के लिए उत्साहित हैं। यह एक विशेष समूह है जिसमें अनुभव और युवा प्रतिभा का शानदार संतुलन है। हमारे कई खिलाड़ी पहले ही सीनियर स्तर पर अपने कौशल का प्रदर्शन कर चुके हैं और उनकी उपस्थिति टीम का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण होगी। हमारा ध्यान आक्रामक, अनुशासित खेल खेलने और मैच दर मैच आगे बढ़ने पर है। हमें अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा है और हमारा मानना ??है कि इस टीम में खिताब की रक्षा करने और देश को फिर से गौरवान्वित करने की क्षमता है।

भारतीय टीम अपना पहला मैच 8 दिसंबर को बांग्लादेश से खेलेगी।

अपने भविष्य को लेकर अभी कुछ नहीं कह सकता : मेसी

ब्यूनस आयर्स

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने कहा है कि मैंने अभी तक अपने भविष्य और संन्यास को लेकर कुछ तय नहीं किया है, इसलिए इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। फीफा विश्व कप 2026 के लिए दक्षिण अमेरिकी क्वालीफायर में बोलिविया के खिलाफ अपनी टीम की 6-0 की जीत में मेसी की अहम भूमिका रही है। मेसी ने इस मैच में अर्जेंटीना की ओर से 10वीं अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक लगायी। इस दौरान मेसी ने कहा कि जब भी वह राष्ट्रीय टीम की ओर से खेलते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होती है।

मेसी ने कहा, यहां आकर हमारे लिए लोगों का समर्थन महसूस करके बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से लोग मेरा नाम पुकारते हैं, उससे मैं बहुत खुश हूं। हम सभी लोगों के साथ जुड़ाव का आनंद लेते हैं और हमें अर्जेंटीना में खेलना बहुत पसंद है। हम इस जीत से उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, मैंने अपने भविष्य के लिए कोई तिथि या समय सीमा तय नहीं की है, मैं बस इसका आनंद लेना चाहता हूं।

मैं यहां आकर और लोगों का प्यार महसूस करके पहले से कहीं अधिक उत्साहित हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे आखिरी खेल हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं क्लब में साल का अंत अच्छे से करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा और फिर हर दिन का आनंद ले पाऊंगा।

मेसी अपने देश की ओर से शीर्ष स्कोरर भी बन गए हैं, जिन्होंने 189 मैचों में 112 गोल किए हैं। सीनियर टीम की ओर से उन्होंने पहला गोल 1 मार्च, 2006 को बेसल में क्रोएशिया के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में किया था।

अर्जेंटीना फुटबॉल वेबसाइट के अनुसार, नेशनल टीम के लिए उनके आधे से अधिक गोल आधिकारिक थे। विश्व कप क्वालीफिकेशन में 34, कोपा अमेरिका में 17 और विश्व कप में 13 और अर्जेंटीना वह देश था जहां उन्होंने सबसे अधिक गोल 34 किए।

अभी से गंभीर की कोचिंग का आंकलन न करें : अजय जडेजा

नई दिल्ली। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने कहा है कि गंभीर को कोच बने अभी कुछ ही समय हुआ है। ऐसे में अभी से ही उनकी कोचिंग का आंकलन करना ठीक नहीं होगा। भारतीय टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली 0-3 की हार के बाद से गंभीर आलोचना का सामना कर रहे हैं। जडेजा ने गंभीर का बचाव करते हुए कहा कि इतने कम समय में किसी के प्रदर्शन का आंकलन करना सही नहीं है। गंभीर ने अपने कार्यकाल की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में जीत के साथ की थी पर इसके बाद टीम को उस दौरे पर एकदिवसीय सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ने इसके बाद टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 से पर हराया पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 ये मिली करारी हार के बाद से ही गंभीर पर सवाल उठने लगे। जडेजा ने कहा कि किसी के प्रदर्शन का आंकलन पर्याप्त समय में ही करें। हमें इस समय उनका मूल्यांकन करने की जगह खेल का आनंद उठाना चाहिए। पर्थ में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की बड़ी जीत से टीम का उत्साह बढ़ा है। जडेजा ने कहा कि हर किसी के साथ उतार-चढ़ाव आते हैं, कभी आप जीतते हैं और कभी आप हारते हैं। इसलिए मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा और छह महीने में उनका गंभीर के कामकाज की समीक्षा नहीं करुंगा।

अहोम राजा सु-का-फा की विरासत के सम्मान में *मनाया जाता है असोम दिवस*

दो दिसंबर को असम उत्सवों से भरा हुआ है क्योंकि राज्य *असोम दिवस* या असम दिवस मनाता है, जो अहोम राजा सु-का-फा की विरासत का स्मरण कराता है। सु-का-फा, जिन्हें सुकफा के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक सम्राट ही नहीं थे, बल्कि एक राजवंश के निर्माता थे, जिसने असम के भाग्य को आकार दिया। 1228 में जन्मे, चुनौतीपूर्ण पटकाई पहाड़ियों पर उनकी यात्रा ने अहोम राजवंश की शुरुआत को चिह्नित किया। उनके शासनकाल ने न केवल राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की, बल्कि सांस्कृतिक आत्मसात को भी बढ़ावा दिया, जिसने क्षेत्र के विविध जातीय समूहों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। सुकफा द्वारा स्थापित अहोम साम्राज्य 1228 से लेकर लगभग छह शताब्दियों तक कायम रहा और इसने असम के अलग-अलग समुदायों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। सुकफा के शासन सिद्धांत सद्भाव, न्याय और एकता पर आधारित थे, जिसने *ग्रेटर असम* को संस्कृतियों और परंपराओं के मिश्रण में ढाल दिया। 2 दिसंबर को 1996 से सुकफा दिवस या असम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो सुकफा की ऐतिहासिक यात्रा और उत्थान का स्मरण कराता है। यह दिन न केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति का सम्मान करता है, बल्कि असम की एकता का भी प्रतीक है, जो सीमाओं से परे है और इसकी सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध ताने-बाने का जश्न मनाता है। राज्य के लिए असाधारण योगदान के सम्मान में सु का फा पुरस्कार 1996 से एक प्रतिष्ठित सम्मान रहा है। राज्य में असम दिवस की भावना को अपनाया जा रहा है, यह उत्सव सु-का-फा की स्थायी विरासत की याद दिलाता है, जो सदियों से चली आ रही एकता, सुशासन और साझा असमिया पहचान को बढ़ावा देता है। पूरे राज्य और जोरहाट के सु का फा क्षेत्र में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए ह

पुष्पा 2 : रिलीज के चार दिन पहले मेकर्स ने फैन्स को दिया तोहफा

अल्लू अर्जुन की फिल्म *पुष्पा 2* को रिलीज होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फैन्स के बीच इस पिक्चर को लेकर जबरदस्त उत्साह है। अल्लू अर्जुन के साथ एक बार फिर से फिल्म में रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली के रोल में नजर आने वाली हैं। हालांकि, फिल्म की रिलीज से पहले ही मेकर्स ने दोनों की झलक दिखा दी है। 1 दिसंबर की शाम मेकर्स ने इस फिल्म का एक नया गाना रिलीज किया है, जिसमें अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना दिखी हैं। गाने का नाम है *पीलिंग्स*। इसमें दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। दोनों का अंदाज फैन्स को पसंद आ रहा है। दोनों की जोड़ी अच्छी तो लग ही रही है, साथ ही दोनों का डांस भी शानदार है। इस गाने के लिरिक्स राकिब आलम ने लिखे हैं। वहीं जावेद अली और मधुबंती बागची ने इस गाने को आवाज दी है। वहीं इस गाने में जो मलयालम हिस्सा है उसे अपर्णा हरिकुमार, इंदु सानथ और गायत्री राजीव ने मिलकर गाए हैं। ये इस फिल्म का कोई पहला गाना नहीं है। इससे पहले मेकर्स ने कुछ और गाने भी रिलीज किए और उन्हें भी ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक गाना है *पुष्पा* का टाइटल सॉन्ग, जिसे *पुष्पा पुष्पा* के नाम से रिलीज किया गया और दूसरा गाना है *किसिक,* जिसमें अल्लू अर्जुन के साथ श्रीलीला दिखीं। वहीं अब मेकर्स ने अल्लू अर्जुन और रश्मिका की जोड़ी एक साथ दिखाई है। बहरहाल, सुकुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अब एक बार फिर से फहाद फासिल भी आईपीएस भंवर सिंह शेखावत के रोल में नजर आने वाले हैं। देखना होगा कि इस बार जब पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत की टक्कर होगी तो क्या होता है।

सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए जरुरी हैं यह विटामिन, इम्यूनिटी होगी मजबूत

सर्दियों में सेहत का ख्याल रखना बेहद जरुरी है। इस मौसम में अक्सर शरीर सुस्त नजर आता है। सर्दी से इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। ठंड में सर्दी-जुकाम और खांसी जैसी बीमारियां बार-बार परेशान करती हैं। दरअसल, ठंड में स्किन शुष्क और संवेदनशील होती है जिस वजह से त्वचा में इर्रिटेशन होने लगती है। शरीर को हेल्दी बनाने के लिए सर्दियों में पोषण की अधिक जरुरत होती है।

विटामिन बी-12 और बी-कॉम्प्लेक्स : सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए अपने आहार में विटामिन लेना जरुरी है। दरअसल,बी- 12 अवाश्यक बी- विटामिन में से एक है। विटामिन बी-12 शरीर की रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है. बी-12 लाल रक्त कोशिका के उत्पादन को बढ़ाता है. यह हमारी बॉडी में उर्जा प्रदान करता है इसके साथ ही स्किन को चमकदार बनाता है. आप अपने डाइट में आंडा, दही, चीज और दूध शामिल कर सकते हैं।

विटामिन डी : सर्दियों में विटामिन डी लेना जरुरी है। कई बार ठंड के मौसम में धूप नहीं निकालती है जिस वजह से शरीर में विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। विटामिन डी एक सनसाइन विटामिन है जो धूप से प्राप्त होती है। विटामिन डी लेने से बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिलते है, शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस प्राप्त होता है। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हड्डियों का विकास करता है।

ओमेगा 3 फैटी एसिड्स : ठंड के मौसम में इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए ओमेगा फैटी एसिड्स की पर्याप्त मात्रा लेना जरुरी है। इसके लिए आप डाइट में शामिल कर सकते हैं कद्दू के बीज, फ्लेक्स सीड, सनफ्लावर सीड, बादाम, अखरोट, फिश आदि।

विटामिन ई : सर्दी में त्वचा काफी शुष्क हो जाती है इसलिए विटामिन ई रिच फूड के सेवन से स्किन कोमल और मॉइस्चराइज होती है। इतना ही नहीं त्वचा की झुर्रियां भी कम होती हैं। आप भोजन में नट्स, पालक, अंडे, चुकंदर, कद्दू, लाल शिमला मिर्च और बीज शामिल कर सकते है।

विटामिन ए : ठंड के मौसम खुद को हेल्दी रखने के लिए डाइट में विटामिन ए होना जरुरी है. विटामिन ए से शरीर को एंटीऑक्सिडेंट मिलता है वहीं यह बॉडी में एंटी इफ्लेमेटरी का प्रभाव डलता है। आप अपने भोजन में शमिल कर सकते हैं सरसों के पत्ते, पालक के पत्ते, बथुआ, गाजर, केल और शकरकंद जैसी सब्जियां। सर्दियों में स्वस्थ शरीर और इम्यूनिटी को स्ट्रॉग करने के लिए अपने भोजन में यह सभी विटामिन अवश्य शमिल करें।

सर्दियों में ठंडे फर्श को गर्म रखने के उपाय

सर्दियों के दौरान ठंड बढ़ने से हर किसी पर असर पड़ता है। बदलते मौसम के कारण कई लोगों को सर्दी, खांसी और गले में खराश जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैसे इन बीमारियों का एक आम कारण ठंडा फर्श है, क्योंकि ठंडी सतह पर चलने से बीमारियां अधिक बढ़ सकती है। सर्दियों के महीनों के दौरान अपने घर को गर्म और आरामदायक बनाए रखने के लिए हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं।

- जब सर्दियां आती हैं तो फर्श ठंड हो जाते हैं। ऐसे में फर्शों को गर्म रखने के लिए इन आसान तरीकों जरुर अपनाना होगा। आप अपने फर्श को गर्म रखने के लिए कालीन या गलीचों का प्रयोग कर सकते है। आप पुराने कपड़ों के प्रयोग करके घर में बनी चटाई बना सकते है। जो इस मौसम में ठंड को कम करने में भी मदद कर सकता है।
- सर्दियों को दौरान कई लोग पानी से या फिर ठंडे पानी में भिगोए कपड़े से पोंछकर साफ करते हैं। ऐसा करने से बीमारियों का अधिक खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अपने फर्श को ठंडे पानी के संपर्क में आए बिना कुशलता पूर्वक साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करें।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : डॉ. आसमां बेगम ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**